सांध्य दैनिक
नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि
PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार

बेईमान आदमी भी चाहता है कि, उसके साथ के आदमी ईमानदार रहें, यही ईमानदारी की ताकत है... ।

अज्ञात...

वर्ष-01 अंक-26 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, शुक्रवार 13 फरवरी 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य -2 रुपए,

आम आदमी पार्टी की सक्रियता का असर : कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत के बाद हरकत में आया निगम

तालाबों की सफाई शुरू

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार चौधरी की पहल और जनदर्शन में की गई शिकायत के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। वार्ड नंबर 23, घासीदास नगर के नवीन स्कूल और उसके समीप स्थित तालाब में फैली गंदगी को लेकर दी गई शिकायत के बाद नगर निगम ने सफाई कार्य शुरू कर दिया है।

क्या है पूरा मामला

वार्ड अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने 9 फरवरी 2026 को कलेक्टर जनदर्शन में लिखित शिकायत दी थी कि घासीदास नगर के नवीन स्कूल परिसर और पास के तालाब में भारी मात्रा में कचरा और गंदगी जमा है। पानी की निकृष्ट के कारण महिलाएं इसी तालाब का उपयोग करती हैं, जिससे गंदगी के कारण बीमारियों का खतरा बना हुआ था। स्थानीय पार्षद द्वारा समस्या पर ध्यान न दिए जाने के बाद 'आप' ने सीधे प्रशासन का दरवाजा खटखटाया।

पार्षदों और विधायक की उदासीनता पर बरसे नेता

आम आदमी पार्टी के नेता जसप्रीत सिंह ने वैशाली नगर क्षेत्र की बदहाल स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा: "वैशाली नगर के वार्डों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। तालाबों का महत्व हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ा है, लेकिन वैशाली नगर के विधायक और पार्षद इनके संरक्षण और सफाई को लेकर गंभीर नहीं हैं। जब तक जनता शिकायत लेकर कलेक्टर के पास नहीं जाती, तब तक स्थानीय जनप्रतिनिधि कुंभकर्णी नींद में सोए रहते हैं।"

आने वाले समय में बदलाव का दावा

पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि विकास कार्यों और स्वच्छता की यही स्थिति रही, तो आने वाले समय में हर वार्ड में आम आदमी पार्टी का पार्षद होगा जो जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करेगा।

शिकायत में शामिल प्रमुख सदस्य

प्रशासन तक अपनी आवाज पहुँचाने वालों में मुख्य रूप से धर्मेंद्र चौधरी, जसप्रीत सिंह, राजकुमार, अविनाश सहित वार्ड के अनेक जागरूक नागरिक उपस्थित रहे।

खास-खबर

संस्कार का छात्र बना गांव का पहला डॉक्टर, हमारा ध्येय बच्चों का जीवन निर्माण-रामचंद्र शर्मा

नई दृष्टिबिंदु / रायगढ़

ग्रामवासियों ने डॉक्टर का फूल-माला से किया स्वागत

शहर की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था संस्कार पब्लिक स्कूल के छात्र नवीन चंद्रा ने अपने गांव का पहला डॉक्टर होने की उपलब्धि पाकर माता-पिता एवं पूरे गांव सहित संस्कार पब्लिक स्कूल को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। संस्था की प्राचार्या श्रीमती रश्मि शर्मा ने बताया कि नवीन चंद्रा ने कक्षा 2री से 12वीं तक कुल 11 साल शिक्षा ग्रहण की।

वह जिला सक्ति के ब्लॉक मालखरौदा के ग्राम मोहतरा के निवासी किसान हरिशंकर चंद्रा एवं श्रीमती कमला चंद्रा का बालक है। जिसने संस्कार पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में प्रवेश लिया। वह प्रारंभ से ही मेधावी छात्र रहा। जिसने गुरूजनों के मार्गदर्शन विशेष कर डायरेक्टर रामचंद्र शर्मा के मोटिवेशन से बहुत प्रभावित हुआ।

नवीन चंद्रा के पिता हरिशंकर चंद्रा ने बताया कि नवीन ग्राम मोहतरा का पहला बेटा है जो डॉक्टर बना। जब वह डॉक्टर की शिक्षा पूर्ण कर गांव पहुंचा तो पूरा गांव स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ा। सबने फूल-मालाओं और जोशिले नारे लगाते हुए नवीन का स्वागत किया। पूरे ग्राम मोहतरा में गांव के बेटे नवीन के डॉक्टर बनने से हर्ष का माहौल है।

मैं अपनी सफलता का श्रेय पूर्ण रूप से रामचन्द्र शर्मा सर एवं संस्कार पब्लिक स्कूल के गुरूजनों को देता हूं। मैं ग्रामीण परिवेष के कारण दबा रहता था लेकिन रामचन्द्र शर्मा सर के मोटिवेशनल स्पीच के कारण आत्म निर्भर एवं आत्म विश्वास से परिपूर्ण हुआ। जिसके चलते सफलता के मुकाम पर पहुंचकर डॉक्टर बना माता पिता के आशीर्वाद तथा रामचंद्र सर एवं संस्कार स्कूल का धन्यवाद।

डॉ. नवीन चंद्रा
छात्र संस्कार स्कूल

परियोजना शाखा में करोड़ों के भ्रष्टाचार मामले की जांच के लिए बनी समिति

खबर का असर

मीडिया दबाव और सियासी घमासान के बाद प्रशासन हरकत में

परियोजना शाखा: विकास का केंद्र या भ्रष्टाचार का अड्डा?

आलोक तिवारी / भिलाई

नगर पालिक निगम भिलाई की परियोजना शाखा का गठन राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं, बड़े पुलों, चौड़ी सड़कों, आधुनिक निर्माण कार्यों और शहर की सुंदरता बढ़ाने वाले विशेष प्रोजेक्ट्स के लिए किया गया था। उद्देश्य था—शहर को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाना। लेकिन आज यही शाखा अपनी मूल भूमिका से भटककर गंभीर सवालों के घेरे में खड़ी है। जिस शाखा से भिलाई के भविष्य की नींव रखी जानी थी, वह आज छोटे-मोटे वृक्षारोपण, वाहन शाखा के कार्य और जोन स्तर के निवेदनों में उलझी नजर आ रही है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि व्यवस्था को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है।

3 फरवरी को नई दृष्टिबिंदु में प्रकाशित खबर – 'परियोजना शाखा: विकास का केंद्र या भ्रष्टाचार का अड्डा?, का बड़ा असर देखने को मिला है। करोड़ों रुपये के पेवर ब्लॉक और अन्य कार्यों में कथित अनियमितताओं को उजागर करने के बाद अब आखिरकार प्रशासन को जांच समिति गठित करनी पड़ी है।

खबर के बाद बढ़ा दबाव

खबर में परियोजना शाखा की कार्यप्रणाली, आयुक्त की भूमिका, निविदा प्रक्रिया में कथित हेरफेर और 12.66 करोड़ के पेवर ब्लॉक कार्यों पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। खबर प्रकाशित होने के बाद– भाजपा संगठन प्रभारी और निगम के भाजपा पार्षदों ने प्रेस-वार्ता कर भ्रष्टाचार के आरोपों को दोहराया। उन्होंने साफ कहा– 'यदि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो जांच में देरी क्यों?' भाजपा पार्षद संतोष मौर्य ने पहले ही शपथ पत्र देकर अपने आरोपों की पुष्टि की थी।

कांग्रेस भी जांच के पक्ष में

घटनाक्रम ने राजनीतिक मोड़ तब लिया, जब अगले ही दिन कांग्रेस पार्षदों और महापौर परिषद के सदस्यों ने भी प्रेस-वार्ता कर एडह जांच की मांग कर दी। अब स्थिति यह बन गई कि– सत्ता और विपक्ष दोनों ही जांच चाहते हैं। फिर सवाल उठा– देरी किसके इशारे पर हो रही थी?

एसडीएम को लेना पड़ा फैसला

सूत्रों के अनुसार, दुर्ग कलेक्टर द्वारा पहले ही छावनी एसडीएम हितेश पिस्दा को जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया। जब नई दृष्टिबिंदु ने 3 फरवरी को एसडीएम का पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने 2-3 दिन में समिति गठन का आश्वासन दिया था। खबर प्रकाशित होने और सियासी दबाव बढ़ने के बाद आखिरकार जांच समिति गठित कर दी गई।

दो सदस्यीय टीम करेगी जांच

गठित जांच समिति में शामिल हैं– आशीष भट्टाचार्य- कार्यपालन अभियंता पीडब्ल्यूडी, जितेंद्र मेश्राम -कार्यपालिन अभियंता आरईएस। यह दो सदस्यीय टीम नगर निगम भिलाई की परियोजना शाखा में लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगी और 15 दिवस के भीतर रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेगी।

अब नजर रिपोर्ट पर

हालांकि सवाल अभी भी बाकी हैं– क्या जांच निष्पक्ष होगी? क्या दोषियों की जिम्मेदारी तय होगी? क्या आयुक्त और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी पड़ताल होगी? क्या 12.66 करोड़ के कथित घोटाले की परतें खुलेंगी?

क्या चेतावनी के बिना नहीं चलता प्रशासन?

पूरे घटनाक्रम से यह भी सवाल उठ रहा है कि– क्या जब तक मीडिया और जनप्रतिनिधि दबाव न बनाएं, तब तक प्रशासन ढिलाई से ही काम करता रहेगा? यदि 3 फरवरी की खबर और उसके बाद राजनीतिक दबाव न बनता, तो क्या जांच समिति बनती?

जनता को अब चाहिए परिणाम

भिलाई की जनता अब केवल जांच समिति गठन से संतुष्ट नहीं है। जनता चाहती है– दोषियों की पहचान, जवाबदेही तय, और सख्त कार्रवाई क्योंकि यह मामला केवल एक शाखा का नहीं, बल्कि नगर निगम की साख और शासन की पारदर्शिता का है।

अधीक्षण और मुख्य अभियंता को लगी कड़ी फटकार

3 फरवरी को नई दृष्टिबिंदु में प्रकाशित खबर के बाद न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल मची, बल्कि प्रशासनिक तंत्र भी हरकत में आ गया। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, जांच समिति गठन के तुरंत बाद नगर निगम आयुक्त ने देर रात तक निगम मुख्यालय में बैठक ली। इस बैठक में अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता को तलब किया गया।

इतने अनुभवी अभियंता, फिर भी विवाद क्यों?

सूत्र बताते हैं कि आयुक्त ने कड़े शब्दों में अधिकारियों से पूछा—नगर निगम भिलाई में इतने अनुभवी अभियंता पदस्थ हैं, फिर भी लगातार जनप्रतिनिधियों द्वारा भ्रष्टाचार के मामले क्यों उठाए जा रहे हैं? स्थिति इतनी गंभीर कैसे हो गई कि जांच के लिए दूसरे विभागों के उच्च अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है? बताया जा रहा है कि आयुक्त ने साफ शब्दों में कहा कि निगम की छवि धूमिल होने पर सीधे जिम्मेदारी तय की जाएगी।

विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि— विकास कार्यों की गति तेज की जाए, गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी सूत्रों के अनुसार, आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया है कि अब हर फाइल और हर भुगतान की प्रक्रिया पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। फटकार के बाद भी सवाल कायम हालांकि अंदरखाने की इस हलचल के बावजूद बड़ा सवाल यही है— क्या केवल फटकार से व्यवस्था सुधरेगी? या जांच रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कार्रवाई होगी? क्योंकि जनता अब केवल बैठकों और निर्देशों से संतुष्ट नहीं है— उसे चाहिए ठोस कार्रवाई और जवाबदेही।

भिलाई निगम के स्वास्थ्य विभाग में RTI उल्लंघन का मामला गरमाया

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भिलाई नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और सूचना के अधिकार (RTI) के निरंतर उल्लंघन के खिलाफ आज जिला कलेक्टर जनदर्शन में एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई गई है। आम आदमी पार्टी के नेता जसप्रीत सिंह ने मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर को संबोधित अपने आवेदन में निगम प्रशासन पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने और फर्जी कर्मचारियों को बचाने का आरोप लगाया है।

मुख्य आरोप और शिकायत के बिंदु

प्रथम अपील के आदेशों की अवहेलना: स्वास्थ्य विभाग के सफाई कर्मियों की सूची मांगने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने 15 दिनों के भीतर जानकारी देने का आदेश दिया था, लेकिन डेढ़ से दो महीने बीत जाने के बाद भी विभाग ने सूची उपलब्ध नहीं कराई है।

सूचना छिपाने की कोशिश

जसप्रीत सिंग का आरोप है कि विभाग द्वारा 'थर्ड पार्टी' और 'अंदाजे से 2000 कर्मचारी' जैसे भ्रामक जवाब देकर भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है।

दोहरे मापदंड

शिकायत में बताया गया कि जहां रिसाली नगर निगम ने 20 दिनों के भीतर सफाई कर्मियों की सूची प्रदान कर दी, वहीं भिलाई निगम जानकारी देने से बच रहा है।

जनदर्शन की विफलता

जसप्रीत ने कहा कि पूर्व में की गई शिकायतों को जब वापस निगम भेजा जाता है, तो अधिकारी तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर देते हैं, जिससे जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है।

लंबित RTI विवरण:

शिकायतकर्ता ने कई महत्वपूर्ण पंजीयन नंबरों का हवाला दिया है जिनका जवाब या तो अप्राप्त है या गोलमाल दिया गया है, जिनमें मुक्तिधाम कमचारी सूची, सफाई कर्मचारी सूची, जोन-4 के डीजल खर्च का विवरण और EPF/ESI की जानकारी शामिल है।

आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि दोषी जन सूचना अधिकारियों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और लंबित सूचनाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं करता, तो वे इस मामले को लेकर न्यायालय (Court) की शरण में जाएंगे।

भ्रष्टाचार

जांच पूरी, कार्रवाई की अनुशंसा भी भेजी गई-फिर भी डेढ़ माह से फाइल अटकी

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास योजना में 65 लाख की अनियमितता का मामला

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना में कथित तौर पर लगभग 65 लाख रुपए की शासकीय राशि में अनियमितता और गबन के मामले में जांच पूरी होने तथा स्पष्ट कार्रवाई की अनुशंसा शासन को भेजे जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस विभागीय कदम नहीं उठाया गया है। इस मामले में तत्कालीन जिला श्रम अधिकारी एनके साहू की भूमिका जांच रिपोर्ट में उल्लेखित होने के बाद भी उनके विरुद्ध न तो निलंबन की कार्रवाई हुई है, न विभागीय जांच प्रारंभ हुई है और न ही किसी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही सामने आई है। करीब डेढ़ माह से फाइल श्रम विभाग स्तर पर लंबित बताई जा रही है, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के क्रियान्वयन में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने विस्तृत जांच कराई थी। जांच के दौरान दस्तावेजों की वैधता, हितग्राहियों की पात्रता जांच, स्वीकृति प्रक्रिया तथा लाभ वितरण में गंभीर त्रुटियां पाई गईं। साथ ही लगभग 65 लाख रुपए की शासकीय राशि के उपयोग और वितरण में अनियमितता के तथ्य सामने आए।

जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर के निर्देश पर अतिरिक्त कलेक्टर, बेमेतरा ने दिसंबर माह में श्रम विभाग के सचिव को विस्तृत पत्र प्रेषित कर तत्कालीन जिला श्रम अधिकारी एनके साहू के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई —निलंबन, रिकवरी और एफआईआर दर्ज करने—की अनुशंसा की थी। नईदृष्टिबिंदु को जांच और अनुशंसा से संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुआ हैं और मामला शासन स्तर तक पहुंच चुका है।

स्थानांतरण के बाद भी कार्रवाई लंबित: जानकारी के अनुसार एनके साहू वर्तमान में धमतरी जिले में पदस्थ हैं। हालांकि प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि स्थानांतरण किसी अधिकारी की जांच या दंडात्मक प्रक्रिया से मुक्त नहीं करता। यदि जांच में भूमिका संदिग्ध पाई गई है तो विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। इसके बावजूद अब तक किसी प्रकार की ठोस प्रगति न होना विभागीय कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगा रहा है।

प्लेसमेंट कर्मचारी पर भी नहीं हुई कानूनी कार्रवाई : मामले में संलिप्त बताए जा रहे एक प्लेसमेंट कर्मचारी को केवल कार्यमुक्त किए जाने की जानकारी मिली है। लेकिन उनके विरुद्ध भी न तो आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है और न ही किसी वैधानिक कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि हुई है। इससे यह चर्चा तेज हो गई है कि कहीं पूरे प्रकरण को धीरे-धीरे ठंडे बस्ते में तो नहीं डाला जा रहा।

जनप्रतिनिधियों ने उठाए सवाल: इस मामले की शिकायतकर्ता स्थानीय भाजपा पार्षद नीतू कोठारी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब जांच पूरी हो चुकी है और जिला प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कार्रवाई की अनुशंसा कर दी है, तो फिर देरी किस कारण से हो रही है? उनका कहना है कि सरकारी योजनाओं में अनियमितता के मामलों में त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई आवश्यक है, अन्यथा जनता के बीच यह संदेश जाता है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना कठिन है।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर प्रश्न: विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना जैसी योजनाएं श्रमिक वर्ग को आवासीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित होती हैं। यदि ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता के आरोप सामने आते हैं और जांच के बाद भी कार्रवाई लंबित रहती है, तो यह न केवल योजना की विश्वसनीयता बल्कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।

सचिव का बदला रुख : मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ श्रम विभाग के सचिव हिमशेखर गुप्ता ने प्रारंभिक स्तर पर इसे जिला प्रशासन से संबंधित विषय बताया था। हालांकि जब उन्हें अवगत कराया गया कि जिला प्रशासन पहले ही कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए पत्र भेज चुका है, तब उन्होंने कहा कि जांच प्रतिवेदन के परीक्षण के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अब शासन के फैसले पर टिकी नजर: करीब डेढ़ माह से लंबित इस प्रकरण ने जिले में प्रशासनिक चर्चा को तेज कर दिया है। जांच रिपोर्ट, कार्रवाई की अनुशंसा और शासन स्तर पर फाइल पहुंचने के बावजूद निर्णय न होना कई सवाल खड़े कर रहा है। अब सबकी नजर शासन के अंतिम फैसले पर टिकी है कि क्या इस मामले में निलंबन, रिकवरी और एफआईआर जैसी अनुशंसित कार्रवाइयों पर अमल होगा या मामला लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया में उलझकर रह जाएगा।

सेल बड़ी छलांग की ओर : बेहतर वित्तीय सूझबूझ से 200 लाख टन बिक्री का तय किया नया लक्ष्य

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक इस्पात कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), भविष्य के लिए एक नई और मजबूत योजना पर काम कर रही है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारना और बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना है। सेल का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने ऋण को कम करना है। इससे कंपनी के पास भविष्य के बड़े निवेशों के लिए ज्यादा पैसा और आजादी होगी। कंपनी अपनी उत्पादन लागत को कम करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने पर ध्यान दे रही है ताकि मुनाफा बढ़ाया जा सके। सेल अपनी पहुंच बढ़ा रही है ताकि देश में स्टील की बढ़ती मांग का फायदा उठाया जा सके। कंपनी ने अपनी इस तरक्की को मापने के लिए एक लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2024-25 में जहां बिक्री 179 लाख टन रही, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में इसे बढ़ाकर के लिए 200 लाख टन का लक्ष्य तय किया गया है।

वित्तीय सूझबुझ और दूरदर्शिता की यह गूंज वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के दौरान की अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान भी सुनाई दी, जहां निदेशक (वित्त) एवं निदेशक वाणिज्य का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे डॉ. ए.के. पंडा ने कंपनी की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने उल्लेख किया कि ऋण में कटौती काफी महत्वपूर्ण रही है, जिसमें अप्रैल-दिसंबर 2025 की नौ महीने की अवधि के दौरान 5,000 करोड़ का ऋण चुकता किया गया है। पिछले साल 31 दिसंबर, 2025 तक ऋण ?24,852 करोड़ था, जिसके बाद जनवरी 2026 में 2,000 करोड़ की और कमी आई। इस अनुशासित ऋण कटौती ने वित्त लागत को कम किया है और विकास निवेशों के लिए अवसर पैदा किए हैं। डॉ. पांडा ने बताया, "परिचालन दक्षता, इन्वेंट्री लिक्विडेशन, लागत अनुकूलन और मजबूत ट्रेजरी प्रबंधन इत्यादि ने मिलकर बेहतर वित्तीय प्रबंधन को संभव बनाया है।"

कंपनी की रणनीति ने पहले ही परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है। कंपनी की सक्रिय मार्केटिंग पहलों और खुदरा एवं नए ग्राहक समूहों के साथ गहरे जुड़ाव के कारण वित्त वर्ष 2025-26 की नौ महीने की अवधि (अप्रैल'25 - दिसंबर'25) में बिक्री की मात्रा में 16.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस प्रयास ने अप्रैल'25 - जनवरी'26 के बीच कुल बिक्री को 16.6 मिलियन टन तक पहुँचा दिया, साथ ही महत्वपूर्ण इन्वेंट्री परिसमापन (inventory liquidation) को भी सक्षम बनाया। सेल ने इन-प्रोसेस और तैयार स्टील स्टॉक दोनों को कम करके, सेल ने नकदी प्रवाह को बढ़ाया है और कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को कम किया, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई।

कंपनी लागत कम करने के लिए ऑपरेशनल लिवर्स को भी तेज किया जा रहा है। सालाना मैनपावर में कमी से प्रति टन कार्मिक लागत दक्षता में लगातार सुधार हो रहा है। इसके साथ ही, सेल अनुपालन की जरूरतों के साथ-साथ लागत कम करने के लिए भी अधिक नवीकरणीय ऊर्जा (renewable power) का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे ऊर्जा व्यय में संरचनात्मक बचत हो रही है। ये उपाय प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करते हुए कंपनी के व्यापक स्थिरता एजेंडे के साथ मेल खाते हैं।

कंपनी के भविष्य के विजन पर सेल के निदेशक (वित्त) एवं निदेशक वाणिज्य का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे डॉ. ए.के. पंडा ने कहाः कंपनी कर्ज कम करके, इन्वेंट्री की अधिक कुशलता से प्रबंधन करके और केंद्रित मार्केटिंग पहलों के मध्यम से अपनी पहुंच का विस्तार करके, विस्तारीकरण की तैयारी के साथ-साथ अपनी नींव को मजबूत कर रहा है। बढ़ती मांग, एक मजबूत कैपेक्स (CAPEX) पाइपलाइन और स्थिरता व ग्रीन स्टील के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता के साथ, हम वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 200 लाख टन की बिक्री हासिल करने और आने वाले वर्षों में और भी ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने के प्रति आश्वस्त हैं - जो आज की ताकत को कल के अवसर में बदल देगा।

कोसानाला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी की घोषित

भिलाई। भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के अनुमोदन पश्चात कोसानाला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरसिंह नाथ ने ब्लॉक कार्यकारिणी की सूची जारी पश्चात कर दी है। कार्यकारिणी में कुल 4 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 3 संयुक्त मंत्री, एक कोषाध्यक्ष, 14 सचिव और दो कार्यकारिणी सदस्यों को शामिल किया गया है।

कोसानाला सुपेला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी इस प्रकार है। अध्यक्ष नरसिंह नाथ, उपाध्यक्ष रूपचंद गुर्जर, बंटू शर्मा, शिव साहू और वासु पांडे, महामंत्री इस्माइल खान, बलदाऊ पिपरिया, नरेंद्र पिपरोल और भानु प्रताप जंघेल, संयुक्त महामंत्री वीर बहादुर थापा आजाद अंसारी और दानवीर देवांगन, कोषाध्यक्ष बुद्ध शरण बोरकर, सचिव अमरजीत सिंह, प्रमोद यादव, मोहन दलाई, संभू साव, मो. अशरफ, संदीप कुमार, नितेश लाउत्रे, राजेश्वर प्रसाद सोनवानी, राजू कन्हाई, लक्की दुबे, कीर्ति सिंह, ललिता साहू, वीणा देशलहरे और अंजलि भवते, कार्यकारिणी सदस्य कृतेश साहू और विक्की कुरैशी।

भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री चंद्राकर ने नए पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं सदस्य एकजुट होकर एक परिवार की तरह कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे। जनहित से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने का भरसक प्रयास करेंगे। भाजपा की हर गलत नीतियों का विरोध सड़क पर उतर कर करेंगे।

मार्ग जाम व शासकीय कार्य में बाधा प्रकरण में एक और आरोपी गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

बिना अनुमति प्रदर्शन कर सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने एवं शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के प्रकरण में दुर्ग पुलिस ने एक अन्य आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पूर्व में 05 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसके साथ ही अब तक कुल 06 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 दिसंबर 2025 को थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पटेल चौक, बीएसएनएल कार्यालय के सामने कुछ व्यक्तियों द्वारा जमीन रजिस्ट्री की बढ़ी हुई दरों के विरोध में बिना किसी पूर्व अनुमति अथवा सूचना के मार्ग अवरुद्ध कर प्रदर्शन किया गया था। मौके पर तैनात पुलिस बल द्वारा समझाइश देने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने उग्र होकर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से हाथापाई की, जिससे शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई एवं आवागमन प्रभावित हुआ। घटना में प्रधान आरक्षक राधेश्याम चंद्राकर, आरक्षक केशव कुमार, तुषार सलामे, अजय साहू एवं हिमांशु जंघेल को चोटें आईं। इस संबंध में थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में अपराध क्रमांक 609/2025, धारा 221, 126(2), 191(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पूर्व में 05 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। प्रकरण के एक अन्य आरोपी मनोज राजपूत (उम्र 50 वर्ष), निवासी सिकोला भाटा, दुर्ग को माननीय उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त होने के उपरांत विधिवत गिरफ्तार किया गया। सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर आरोपी को जमानत मुचलका पर रिहा किया गया है। पुलिस द्वारा शेष फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

गिरफ्तार आरोपी में अनिल वासनिक (43), निवासी अंबेडकर नगर, दुर्ग, विक्की चंद्राकर (32), निवासी शीतला नगर, दुर्ग, दिनेश पाण्डेय (35), निवासी गयानगर, दुर्ग, राकेश यादव (38), निवासी गयानगर, दुर्ग, जितेन्द्र बत्रा (41), निवासी सिंधी कॉलोनी, स्टेशन रोड, दुर्ग, मनोज राजपूत (50), निवासी सिकोला भाटा, दुर्ग शामिल हैं। वहीं फरार आरोपी में शुभम सिंह राजपूत, यशवंत सिंह राजपूत, ओमप्रकाश कोटवानी, गीतेश ठाकुर एवं अन्य है। इस कार्रवाई में थाना सिटी कोतवाली दुर्ग के प्रधान आरक्षक राधेश्याम चंद्राकर, आरक्षक केशव कुमार, आरक्षक तुषार सलामे, आरक्षक अजय साहू, आरक्षक हिमांशु जंघेल सहित थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही। दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, सभा अथवा धरना हेतु विधिसम्मत अनुमति अवश्य प्राप्त करें। कानून हाथ में लेने, सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने एवं शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कान्फ्रेंस आज

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

शासकीय नर्सिंग कॉलेज, दुर्ग (स्व. चंदूलाल चंद्राकर शासकीय मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग) की ओर से एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कान्फ्रेंस (हाइब्रिड मोड) का आयोजन 14 फरवरी शनिवार को सुबह 11 बजे से कला मंदिर, सिविक सेंटर भिलाई में किया गया है।

आयोजन की चेयरपर्सन और नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. रीमा राजेश ने बताया कि दिन भर चलने वाली इस कान्फ्रेंस का विषय सीमाओं से परे नर्सिंगः स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्टता लाने वाला गुणात्मक अनुसंधान रखा गया है। आयोजन सचिव सपना ठाकुर एसोसिएट प्रोफेसर गवनर्मेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग दुर्ग, समन्वयक डॉ. वंदना चौहान एसोसिएट प्रोफेसर गवनर्मेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग दुर्ग,डॉ. ममता शशि साहू एसोसिएट प्रोफेसर गवनर्मेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, दुर्ग,डॉ. कल्पना भूषण जोशी एसोसिएट प्रोफेसर गवनर्मेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग दुर्ग तैयारियों में जुटे हैं।

इस दौरान विभिन्न सत्रों में प्रमुख रूप से डॉ. नैन्सी फर्नांडीस परेरा एकेडमिक एडवाइजर, एसएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वापी, पूर्व प्रिंसिपल, एलटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएनडीटी यूनिवर्सिटी, मुंबई,चेयरपर्सन डॉ. भावना चक्रवर्ती एसोसिएट प्रोफेसर गवनर्मेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, दुर्ग, डॉ. विष्णु रंजीत और रंजुला यशोधरन, डॉ. जिबी जॉर्ज सीईओ आदेश्वर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जगदलपुर और डॉ. कल्पना भूषण जोशी एसोसिएट प्रोफेसर, गवनर्मेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग दुर्ग, मार्गदर्शन देंगे। समापन समारोह में प्रमाणपत्र वितरण व अन्य आयोजन होंगे।

4 माह से पेंशन नहीं, एमआईसी ने लिखा समाज कल्याण विभाग को पत्र

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

पेंशन धारियों के खातें में राशि नहीं आने से महापौर परिषद ने समाज एवं कल्याण विभाग को पत्र लिखा है। रिसाली महापौर शशि सिन्हा ने कहा पेंशन हितग्राहियों को पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। परिषद के सदस्यों ने बैठक में 305 नए आवेदनों को अनुमोदन भी किया।

दरअसल परिषद के सदस्यों का कहना था कि नवम्बर 2025 से पेंशन हितग्राहियों के खाते में राशि नहीं आई है। चर्चा के दौरान खुलासा हुआ कि विभाग से ही राशि का आवंटन नहीं हुआ है। इसे

महापौर परिषद के सदस्यों ने गंभीरता से लिया और समाज कल्याण विभाग को पत्र लिखने का निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय पेंशन एवं राज्य शासन की पेंशन योजना के तहत वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन के तहत 500-500 और समाजिक सुरक्षा के तहत 49 वर्ष से कम आयु में विधवा होने पर 20 हजार की सहायता दी जाती है। योजना का लाभ लेने बी.पी.एल. होना अनिवार्य है। महापौर परिषद की बैठक में महापौर शशि सिन्हा, एमआईसी संजू नेताम, जहीर अब्बास, अनिल देशमुख, रोहित धनकर, आयुक्त मोनिका वर्मा, कार्यपालन अभियंता सुनील दुबे समेत विभाग प्रमुख उपस्थित थे।

305 आवेदनों का अनुमोदन

महापौर परिषद के सदस्यों ने अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक प्राप्त 305 पात्र आवेदनों का अनुमोदन किया। पात्र में केन्द्रीय पेंशन योजना के 247 एवं राज्य पेंशन योजना के 58 लोग शामिल है।

अधिवक्ता संघ चुनाव के लिए अधिवक्ता राजीव पांडेय बने मुख्य चुनाव अधिकारी

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

गुरुवार 12 फरवरी को समय 12:30 बजे संघ की मीटिंग आहूत की गई। मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया की जिला अधिवक्ता संघ, दुर्ग की आगामी चुनाव वर्ष 2026-2028 हेतु मुख्य चुनाव अधिकारी हेतु राजीव पाण्डेय, उपमुख्य चुनाव अधिकारी हेतु इशराईल शरीफ, साथ ही अपीलीय अधिकारी हेतु राजकुमार तिवारी, शिवशंकर सिंह, तेजपाल सिंह, डी. एस. राजपुत, मोह. अरशद खान को अपीलीय अधिकारी नियुक्त करने बाबत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है'।

जिला प्रशासन द्वारा अवैध उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

जिला प्रशासन द्वारा मुरूम एवं रेत के अवैध उत्खनन के संबंध में जनता की शिकायत पर आज बड़ी कारवाई की गई है। इसके तहत अवैध उत्खनन में संलिप्त एक जेबीसी मशीन तथा अवैध उत्खनन परिवहन में संलिप्त एक ट्रेक्टर एवं चार हाईवा वाहन जब्त किये गये है।

कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार एसडीएम पाटन लवकेश ध्रुव ने रानीतराई-पाटन के समीप जेसीबी द्वारा अवैध उत्खनन करते हुए पाये जाने और ट्रेक्टर द्वारा परिवहन करते पाये जाने पर उक्त जेसीबी मशीन और ट्रेक्टर को जब्त किया है। इसी प्रकार राजस्व विभाग के टीम द्वारा तहसीलदार पाटन के नेतृत्व में बालोद-धमतरी से रेत परिवहन करते पाये

जाने पर चार हाईवा वाहन को जब्त कर थाना प्रभारी रानीतराई को पुलिस अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया है। एसडीएम श्री ध्रुव ने बताया कि क्षेत्र में अवैध ईट भट्ठों के संचालकों को भी बगैर अनुमति के ईट भट्ठे लगाकर पर्यावरण प्रदूषित करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। अवैध उत्खनन और ईट भट्ठों पर आगे भी निरंतर कारवाई जारी रहेगी।

भव्य मंडाई मिलन समारोह में शामिल हुए दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

ग्राम डुडेरा में भव्य मंडाई मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग ग्रामीण विधायक व राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर सम्मिलित हुए और देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया और विधिवत मंडाई मेला का शुभारंभ किया।

रात्रिकालीन प्रोग्राम रंग सरोवर का अनुपम प्रस्तुति हुआ, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। रंग सरोवर कार्यक्रम में संगीत, नृत्य और नाटक की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम ने मंडाई मेला को और भी आकर्षक बना दिया और ग्रामवासियों को एक यादगार शाम

प्रदान की।

इस अवसर पर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने अपने उद्बोधन में कहा, "किसान भाईयों के लिए फसल कटाई का समय एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। फसल कटाई के बाद, जब खेतों में हरियाली की जगह सुनहरा रंग ले लेता है, तो यह समय होता है जब किसान अपने परिवार और समाज के साथ मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। मंडाई मेला इसी खुशी और उत्साह का प्रतीक है।"

उन्होंने आगे कहा, "मंडाई मेला न केवल हमारी पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा देता है, बल्कि यह हमारे समाज में एकता और भाईचारे को भी मजबूत बनाता है। यह आयोजन हमें अपने समाज और परिवार के साथ जोड़ता है और हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने का अवसर प्रदान करता है। मैं इस आयोजन के लिए ग्रामवासियों को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह परंपरा आगे भी जारी रहेगी।" इस अवसर पर प्रमुख रूप से मरोदा-पुर्रेना मंडल अध्यक्ष राजू राकेश जंघेल, विधायक प्रतिनिधि गोविंद राम साहू, पार्षद खिलेंद्र विक्की चंद्राकर, पार्षद रोहित धनकर, चंद्रशेखर, छाया पार्षद दुर्गेश साहू, इंद्रजीत सोनी, नंदू साहू, केशव महीपाल, तरुण बंजारे, पवन कुमार, ओंकार मार्कण्डेय, रमेश जैन, शिव साहू, धीरज साहू, चंदू गायकवाड़, चेतन सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।

बिजली उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ याचिकाओं पर जन-सुनवाई

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 के लिए बिजली दरों (टैरिफ) के निर्धारण और राज्यस आवश्यकताओं से संबंधित याचिकाओं पर दुर्ग क्षेत्र(दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा जिले) के उपभोक्ताओं के लिए जन-सुनवाई आयोजित की जा रही है।

सीएसईआरसी द्वारा पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य के दूर-दराज क्षेत्रों के विभिन्न उपभोक्ताओं को उक्त जनसुनवाई की प्रक्रिया में हिस्सा लेने हेतु क्षेत्रवार ऑनलाईन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य की बिजली कंपनियों (उत्पादन, पारेषण, वितरण एवं लोड डिस्पैच सेंटर) द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं पर आम जनता, किसान और उद्योगपति अपने सुझाव व आपत्तियाँ दर्ज करा सकते हैं।

रायपुर कार्यालय में प्रत्यक्ष जन-सुनवाई

यदि कोई उपभोक्ता सीधे रायपुर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी बात रखना चाहता है, तो दिनांक 19 फरवरी 2026 को दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक कृषि एवं कृषि संबंधी कार्य, दोपहर 02:30 से 04:00 बजे तक घरेलू उपभोक्ता एवं सायं 04:00 से 05:30 बजे तक गैर-घरेलू उपभोक्ता उपस्थित होकर अपनी आपत्तियां एवं सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी तरह 20 फरवरी 2026 को दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक स्थानीय निकाय, नगर निगम एवं ट्रेड यूनियन आदि, दोपहर 02:30 से 04:00 बजे तक निम्न दाब उद्योग एवं सायं 04:00 से 05:30 बजे तक उच्च दाब उद्योग अपनी सुझाव प्रस्तुत कर सकेंगे।

याचिकाओं का विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर उपलब्ध है। दुर्ग क्षेत्र के सभी इच्छुक सम्मानीय उपभोक्ता और विभिन्न संगठन इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा बनकर अपने सुझाव दे सकते हैं।

दुर्ग क्षेत्र के लिए ऑनलाइन जन-सुनवाई

दुर्ग क्षेत्र के उपभोक्ताओं को आयोग के रायपुर कार्यालय से सीधे जुड़ने के लिए दिनांक 17 फरवरी 2026 को प्रातः 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रायपुर नाका दुर्ग स्थित मुख्य अभियंता/कार्यालक निदेशक कार्यालय, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, दुर्ग पर उपस्थित हो सकते हैं।

लाभान्वित किसानों से 22,000 रुपये प्रति टन की दर से हो रही है सीधी खरीदी

ऑयल पाम की खेती से खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता की ओर छत्तीसगढ़

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

खाद्य तेल में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ में ऑयल पाम की खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में अब तक 10,796 हेक्टेयर क्षेत्रों में ऑयल पाम की खेती हो रही है। जिसमें 7,315 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। जिला प्रशासन भी ऑयल पाम के लिए जमीन चिह्नांकित कर रकबा बढ़ाने प्रयासरत हैं।

इसी क्रम में संचालक उद्यानिकी लोकेश कुमार ने दुर्ग एवं बेमेतरा जिलों के किसानों के खेतों का निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिक क्षेत्र में ऑयल पाम लगाने के लिए किसानों को प्रेरित किया। उद्यानिकी संचालक लोकेश कुमार ने निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन, समेकित उद्यानिकी विकास कार्यक्रम तथा नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम के अंतर्गत

किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया।

गौरतलब है कि राज्य में ऑयल पाम की खेती वर्ष 2012-13 से की जा रही है। वर्तमान में राज्य के समस्त जिलों में लगभग 10,796 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण किया जा चुका है, जिससे 7,315 किसान लाभान्वित हुए हैं। अब तक लगभग 1,394.88 टन फ्रेश फ्रूट बंच का उत्पादन हुआ है। भारत सरकार द्वारा फ्रेश फ्रूट बंच का न्यूनतम मूल्य 16,460.46 रुपये प्रति टन निर्धारित कया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ में किसानों से 22,000 रुपये प्रति टन की दर से सीधी खरीदी की जा रही है।

संचालक लोकेश कुमार ने दुर्ग जिले के ग्राम ढाबा में श्रीमती सुनिती देवी मढ़रिया के एक हेक्टेयर में लगाए गए ऑयल पाम के साथ टमाटर की अंतरवर्ती फसल तथा प्रवीण मढ़रिया के एक हेक्टेयर क्षेत्र में ऑयल पाम के साथ केले की खेती का अवलोकन किया। यहां किसानों से सब्सिडी और अनुदान से जुड़ी जानकारी साझा की। इसके पश्चात दुर्ग जिले के ही परसदापार, चिखला एवं राजपुर तथा बेमेतरा जिले के डोंगीतराई गांव में चयनित और लाभान्वित किसानों के खेतों में रोपित ऑयल पाम, केला, आम, फेंसिंग और अंतरवर्ती फसलों का अवलोकन किया।

संचालक लोकेश कुमार ने किसानों को योजना के अंतर्गत ऑयल पाम पौध, फेंसिंग, ट्यूबवेल, ड्रिप सिंचाई तथा अंतरवर्ती फसलों पर मिलने वाली आर्थिक सहायता और उत्पाद की बाजार व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऑयल पाम की खेती किसानों की आय बढ़ाने का बेहतर विकल्प बन रही है। राजपुर स्थित शासकीय बीज प्रगुण प्रक्षेत्र में प्लग टाइप सीडलिंग यूनिट का निरीक्षण कर इसे शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए, ताकि आगामी मौसम में किसानों को गुणवत्तायुक्त पौध उपलब्ध कराई जा सके।

खास खबर

बैंक ऑफ महाराष्ट्र व शासन के मध्य उन्नत वेतन पैकेज के लिए हुआ एमओयू

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार के नियमित कमर्चारियों को आकर्षक एवं व्यापक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ शासन के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत बैंक में वेतन खाता संचालित करने वाले राज्य सरकार के सभी नियमित कमर्चारियों को गवर्नमेंट प्राइड सैलरी सेविंग स्कीम के अंतर्गत उन्नत निःशुल्क सुविधाएं एवं बीमा कवर प्रदान किए जाएंगे।

समझौते के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा खाताधारक कमर्चारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा एक करोड़ 25 लाख रूपए तक, हवाई दुर्घटना बीमा एक करोड़ रूपए तक, स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर एक करोड़ 25 लाख रूपए तक तथा टर्म इंश्योरेंस 10 लाख रूपए प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही गोल्डन आवर के अंतर्गत 1 लाख रूपए तक कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध होगी। कमर्चारियों को बालिका विवाह लाभ 10 लाख रूपए तक एवं बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु 10 लाख रूपए तक का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त खाताधारकों को अन्य आकर्षक बैंकिंग लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे तथा स्वास्थ्य बीमा पर टॉप-अप जैसी वैकल्पिक सुविधाएं रियायती दरों पर प्रदान की जाएंगी। यह समझौता ज्ञापन 10 फरवरी 2026 को श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा, विशेष सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा वी. वेंकटेश, अंचल प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रायपुर अंचल की उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह पहल राज्य सरकार के नियमित कमर्चारियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक एवं लाभप्रद बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से सुदृढ़ हो रही किसानों की आर्थिक स्थिति

रायपुर। सरकार की किसान हितैषी योजनाएं जिले के कृषकों के लिए सशक्त संबल सिद्ध हो रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को प्राप्त हो रही नियमित आर्थिक सहायता उनके कृषि कार्यों को मजबूती प्रदान कर रही है। कोरबा जिले के ग्राम रिसदा निवासी कृषक गोवर्धन सिंह इसके उदाहरण हैं। गोवर्धन सिंह पिछले कई वर्षों से खेत करते हैं। उनके पास लगभग चार एकड़ कृषि भूमि है, जिसमें वे मुख्य रूप से धान की फसल लेते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद वे निरंतर परिश्रम कर अपनी आजीविका सुदृढ़ बना रहे हैं। श्री सिंह, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राही हैं। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि सीधे उनके बैंक खाते में समय पर जमा हो जाती है। उन्हें प्रतिवर्ष तीन किश्तों में दो-दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। यह राशि बीज, खाद एवं अन्य कृषि आदानों की पूर्ति में सहायक सिद्ध होती है। उन्होंने बताया कि समय पर आर्थिक सहायता मिलने से उन्हें साहूकारों या अन्य स्रोतों से उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

धन-धान्य से पुष्पित-पल्लवित धरा को सुंदर, समृद्ध, सुरक्षित और विकसित बनाने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही हमारी सरकार : मुख्यमंत्री

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर प्रदेश है और धन-धान्य से पुष्पित-पल्लवित इस धरा को हमारी सरकार सुंदर, समृद्ध, सुरक्षित और विकसित बनाने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने निवास कार्यालय में सिक्किम राज्य से अध्ययन भ्रमण पर पहुंचे पत्रकारों के दल से मुलाकात कर आत्मीय संवाद किया और उनसे छत्तीसगढ़ को लेकर ढेर सारी बातें साझा की। उन्होंने सभी अतिथियों को राजकीय गमछा भेंट कर छत्तीसगढ़ में स्वागत और अभिवादन किया। मुख्यमंत्री की सहृदयता और आतिथ्य पाकर सभी पत्रकार अभिभूत हुए और उन्हें सिक्किम आने का निमंत्रण भी दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ 44 प्रतिशत वन क्षेत्र से आच्छादित है तथा यहां 31 प्रतिशत आदिवासी समुदाय निवासरत है। वनोपज संग्रहण और मूल्य संवर्धन के माध्यम से जनजातीय समुदाय आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। जशपुर जिले में स्व-सहायता समूह की महिलाएं जशआर ब्रांड के अंतर्गत उत्पाद तैयार कर आय अर्जित कर रही हैं। उन्होंने बताया कि तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए सरकार द्वारा 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान किया जा रहा है तथा चरण पादुका योजना के तहत निःशुल्क चप्पल प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह की चिंता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2005 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। हाल ही छह हजार से अधिक जोड़े इस योजना के अंतर्गत विवाह बंधन में बंधे, जिसे

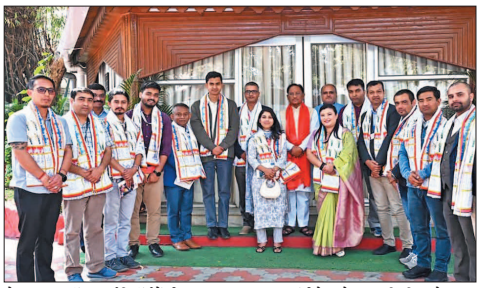

गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत नवदंपतियों को 35 हजार रुपये की आर्थिक सहायता एवं 15 हजार रुपये का सामग्री सहयोग प्रदान किया जाता है।

नक्सलवाद के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सफल नेतृत्व और दृढ़ इच्छाशक्ति के चलते प्रदेश में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है। राज्य सरकार की आकर्षक पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 50 हजार रुपये की सहायता तथा तीन वर्षों तक प्रति माह 10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। अब तक 2,500 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें रोजगार से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। श्री साय ने बताया कि जगदलपुर में आत्मसमर्पित नक्सलियों द्वारा बस्तर पंडुम कैफे का सफल संचालन इसका सशक्त उदाहरण है।

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत 17 शासकीय योजनाओं को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाया गया है, जिससे सड़क, बिजली, पानी, राशन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की पहुंच सुदृढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र अब विकास की मुख्यधारा से तेजी से जुड़ रहे हैं। पर्यटन की संभावनाओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। चित्रकोट जलप्रपात, कुटुम्बसर गुफाएं, अबूझमाड़ के वन और धुड़मारास जैसे स्थल प्रदेश की पहचान हैं। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु होम स्टे को उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिसके तहत ग्रामीणों को पांच कमरों तक निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य एवं औद्योगिक विकास के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि नवा रायपुर में 100 एकड़ क्षेत्र में मेडिसिटी का निर्माण किया जा रहा है, जहां निम्न आय वर्ग के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने प्रदेश की आकर्षक नवीन औद्योगिक नीति का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत राज्य को लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। साथ ही चित्रोत्पला फिल्म सिटी की स्थापना से प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

छत्तीसगढ़ ने भारतीय होने का गर्व कराया-अर्चना प्रधान

सिक्किम की पत्रकार सुश्री अर्चना प्रधान ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मेक इन इंडिया का प्रभावी स्वरूप देखने को मिला। भिलाई स्टील प्लांट में रेल पटरियों सहित विभिन्न इस्पात उत्पादों का निर्माण प्रदेश के औद्योगिक सामर्थ्य को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के औद्योगिक इकाइयों को हमें करीब से देखने का मौका मिला और हम जान पाए है कि इस प्रदेश का देश के विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान है।

पत्रकारों को भाया छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री से भ्रमण उपरांत मिलने पहुंचे पत्रकारों ने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और लोगों का आत्मीय व्यवहार अत्यंत प्रभावित करने वाला है। उन्होंने भ्रमण के दौरान प्राप्त अनुभवों को साझा करते हुए स्थानीय खान-पान और सांस्कृतिक विरासत की सराहना की। सिक्किम से आए पत्रकारों ने अपने पांच दिवसीय भ्रमण के दौरान भिलाई स्टील प्लांट, गेवरा ओपन माइंस, नवा रायपुर तथा जनजातीय संग्रहालय का अवलोकन किया। पत्रकारों ने बताया कि छत्तीसगढ़ भ्रमण की सुंदर स्मृतियों को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, जो उन्हें आजीवन याद रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, किसानों के हित में की गई घोषणाओं, स्वच्छ वातावरण तथा पुनर्वास नीति की सराहना की।

मुख्यमंत्री को भेंट किया सिक्किम का स्मृति चिन्ह थांका

पत्रकारों के दल ने मुख्यमंत्री को सिक्किम की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक थांका पेंटिंग भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस उपहार के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे स्नेह और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का प्रतीक बताया।

पत्रकारों ने बताया कि सिक्किम का थांका पेंटिंग एक पवित्र स्मृति चिन्ह है, जो सूती या रेशमी कपड़े पर बौद्ध देवताओं, मंडलों और बुद्ध के जीवन दृश्यों को दर्शाता है। यह हस्तनिर्मित कला सिक्किम की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, जिसे अक्सर घर की सजावट और सकारात्मक ऊर्जा के लिए लाया जाता है। इन्हें रोल करके आसानी से ले जाया जा सकता है, जो यात्रियों के लिए एक बेहतरीन सोवेनियर है। यह पारंपरिक कलाकृति सिक्किम के निवासियों के लिए धार्मिक विश्वास और आस्था का प्रतीक है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा, मुख्यमंत्री के सलाहकार आर. कृष्णा दास, मुख्यमंत्री के प्रेस अधिकारी आलोक सिंह, पीआईबी गंगटोक के सहायक निदेशक मानस प्रतिम शर्मा, पीआईबी रायपुर के सहायक निदेशक सुदीप्तो सर, पुरुषोत्तम झा और सरद बसनेत, पत्रकार बेनु प्रकाश तिवारी, विकास क्षेत्री, होमनाथ दाबरी, ईश्वर, सुश्री अर्चना प्रधान, सुश्री अनुशीला शर्मा, प्रकाश अधिकारी, ललित दहल, विनोद तमंग, मोहन कुमार कार्की, नार बहादुर क्षेत्री उपस्थित थे।

जिले के अंतिम छोर बोड़ेगाँव पहुँचा सर्विस ऑन व्हील्स सेवा रथ, हितग्राहियों को मिला लाभ

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मोहला-मानपुर-चौकी जिले में संचालित सर्विस ऑन व्हील्स (दिव्यांगजन एवं वृद्धजन सेवा रथ) बुधवार को जिले के अंतिम छोर, महाराष्ट्र सीमा से लगे दूरस्थ एवं सीमावर्ती ग्राम बोड़ेगाँव पहुँचा। प्रशासन की इस संवेदनशील पहल से ग्रामीणों में उत्साह का वातावरण देखा गया। पूर्व में जहां शासकीय योजनाओं का लाभ लेने हेतु ग्रामीणों को दूरस्थ मुख्यालय तक जाना पड़ता था, वहीं अब सेवाएं सीधे गाँव तक पहुँच रही हैं।

सेवा रथ के माध्यम से दिव्यांगजन एवं वृद्धजनों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। इस दौरान 48 डीएलसी भौतिक सत्यापन, 34 आधार सीडिंग, 32 वय वंदन योजना पंजीयन तथा 23 हितग्राहियों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस प्रकार कुल 137 हितग्राही लाभान्वित हुए। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को नशामुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए इसे दूरस्थ क्षेत्र के लिए उपयोगी एवं राहतकारी कदम बताया।

मेला स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सशक्त माध्यम-कश्यप

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

नारायणपुर में आयोजित ऐतिहासिक माता मावली मेले में छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप तथा राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने माता मावली की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों, विशेषकर जिलेवासियों को शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि मावली माता के आशीर्वाद से बस्तर की समृद्ध लोकसंस्कृति और परंपराएं सदैव अक्षुण्ण रहें। उन्होंने कहा कि नारायणपुर का यह मेला सामाजिक समरसता, लोककला और परंपरा का जीवंत संगम है, जहां दूर-दूर से लोग पहुंचकर बस्तर की

संस्कृति से रूबरू होते हैं। उन्होंने सभी को मेले में शामिल होकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने का आग्रह किया।

मंत्री ने मेले में लगे विभिन्न दुकानों एवं विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया तथा स्थानीय उत्पादों और पूजा सामग्री की खरीदारी भी की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करते हैं। इस अवसर पर कुल 1 करोड़ 76 लाख 59 हजार रुपये के कार्यों का भूमिपूजन तथा 59 लाख 51 हजार रुपये के कार्यों का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 10 प्राथमिक शाला भवनों के निर्माण हेतु भूमिपूजन किया गया, जिनकी स्वीकृत राशि 1 करोड़ 41 लाख 60 हजार रुपये है। इसके अलावा जनपद पंचायत ओरछा के ग्राम कुतुल एवं जाटलूर में दो-दो बाजार शेड निर्माण के लिए 34 लाख 99 हजार रुपये स्वीकृत किए गए।

जनपद पंचायत नारायणपुर अंतर्गत बागडोंगरी, पालकी और महिमागवाड़ी में 59 लाख 51 हजार रुपये की लागत से निर्मित खाद्यान्न भवनों का लोकार्पण किया गया। साथ ही नेलवाड़ और खोड़गांव में 100-100 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष रूपसाय सलाम, जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगरपालिका अध्यक्ष इंद्रप्रसाद बघेल, कलेक्टर नम्रता जैन, पुलिस अधीक्षक सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी व नागरिक उपस्थित थे।

श्रममंत्री देवांगन ने ली श्रम विभाग की बैठक, दिए दिशा-निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने गुरुवार को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में श्रम विभाग की दो चरणों में मैराथन समीक्षा बैठक ली। प्रथम चरण की बैठक में श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले तीनों मंडलों की योजनाओं और कारखानों में श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई। मंत्री श्री देवांगन ने अधिकारियों को निर्देश दिए की कारखाने की नियमित तौर पर निरीक्षण करें। श्रमिकों की हितों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। कमी मिलने पर संबंधित उद्योग को निर्देशित करें। हर महीने किए जाने वाले निरीक्षण की भी समीक्षा करने की निर्देश दिए गए।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों को श्रम मंत्री ने कहा कि श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं का

क्रियान्वयन, उनके हितों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा अनुरूप श्रमिक भाई बहनों को योजनाओं के ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलवाए, सुरक्षा के मानको का पूरा ख्याल रखने का प्रयास करें। श्रमिकों के पंजीयन, नवीनीकरण, और योजनाओ का क्रियान्वयन समय अवधि में पूर्ण करें। बैठक में श्रम विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, उप सचिव विपुल गुप्ता, अपर श्रमायुक्त एस. एल. जांगड़े, श्रीमती सविता मिश्रा, बीओसी सचिव गिरीश रामटेके सहित जिलो से आए मैदानी अधिकारी उपस्थित रहे।

श्रम मंत्री ने कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक अधिनियम को लेकर विशेष निर्देश दिए गए। इस अधिनियम के तहत पंजीकृत श्रमिकों को ईएसआईसी और पीएफ का लाभ सुनिश्चित करने साथ ही श्रमिकों की संख्या का मिलान करने के भी निर्देश दिए गए। ठेकेदार को जितने श्रमिकों का लाइसेंस प्राप्त है, उतने ही श्रमिक कार्यरत है की नहीं यह सुनिश्चित करने कहा गया। इसके साथ-साथ निजी कंपनियों से सेवानिवृत हो चुके कर्मियों के उपादन भुगतान संबंधी मामले के जल्द निराकरण, विभिन्न माध्यमों से आने वाले शिकायतों का समय अवधि में निराकरण, करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री की घोषणा शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के अंतर्गत किफायती दर पर भोजन केंद्र की भी समीक्षा की गई। प्रदेश के साथ जिलों में जल्द ही श्रम अन्न केंद्र प्रारंभ करने निर्देश दिए गए। इनमें मुंगेली, सक्ति, जगदलपुर, कांकेर, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, जशपुर और जगदलपुर में केंद्र शुरू करने कहा गया है।

श्रमिकों के स्वास्थ्य के नियमित जांच करने की निर्देश

दूसरे चरण की बैठक में मंत्री लखनलाल देवांगन ने कमर्चारी राज्य बीमा सेवाएं और औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। श्रम मंत्री श्री देवांगन ने सभी जिलों के डिस्पेंसरी की समीक्षा की। ओपीडी की संख्या को और बढ़ाने और श्रमिकों के गुणवत्तापूर्ण इलाज के निर्देश दिए गए।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना : धुएँ से मिली मुक्ति, समय की हो रही बचत

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनांतर्गत गैस कनेक्शन से महिलाओं को धुएं से मुक्ति तथा उनके जीवन स्तर में सुधार आधार आ रहा है। मुंगेली जिले की अनेक महिलाओं को रसोई में लकड़ी और उपलों के धुएँ से भरी, आँखों में जलन और साँसों में तकलीफ सहित अनेक समस्याएं होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 ने इस तस्वीर को बदल दिया है। आज वही रसोई स्वच्छ, सुरक्षित और सम्मान से भरी हुई है। जिले में 01 लाख 22 हजार 545 से अधिक हितग्राहियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

नगर पंचायत सरगांव की श्रीमती रंजित वर्मा ने बताया कि वे पहले लकड़ी और कंडे से खाना बनाती थीं। घर के भीतर धुएँ का भारी गुबार भर जाता था, जिससे

आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती थीं। साथ ही, लकड़ी इकट्ठा करने और चूल्हे पर खाना पकाने में अत्यधिक समय लग जाता था, जिससे समय पर भोजन भी नहीं बन पाता था। अब गैस कनेक्शन मिलने के बाद उनके घर में धुएँ से पूरी तरह राहत मिल गई है। समय की बचत हो रही है और परिवार को समय पर स्वच्छ व सुरक्षित भोजन मिल पा रहा है। पांच सदस्यीय परिवार की गृहिणी रंजिता वर्मा ने इस योजना को अपने जीवन के लिए वरदान बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

खुशी की लहर अब तक 14,518 किसानों को मिला 51.51 करोड़ का भुगतान

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने होली से पहले कर्वधा के गन्ना किसानों को सौगात

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

होली पर्व से पूर्व कवर्धा के गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी सामने आई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित, राम्हेपुर (कवर्धा) द्वारा गन्ना किसानों के लिए 4.73 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। अब तक कुल 14,518 गन्ना किसानों को 51.51 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। नियमित एवं समयबद्ध भुगतान की इस प्रक्रिया से किसानों को आर्थिक संबल मिला है, जिससे वे आगामी कृषि कार्यों की तैयारी सुचारू रूप से कर पा रहे हैं। कलेक्टर एवं कारखाने के प्राधिकृत अधिकारी गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में भुगतान प्रक्रिया निरंतर जारी है। उनके निर्देशन में कारखाना प्रबंधन द्वारा किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए पारदर्शी एवं त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। इससे सहकारी व्यवस्था में किसानों का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है।

कारखाना प्रबंधन ने बताया कि चालू पेराई

सत्र में अब तक 2,42,990 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई की जा चुकी है तथा 2,86,743 क्विंटल शक्कर का उत्पादन किया गया है। यह उपलब्धि किसानों के सतत सहयोग, जिला प्रशासन के मार्गदर्शन और कारखाने की बेहतर कार्यक्षमता का संयुक्त परिणाम है। गौरतलब है कि होली जैसे प्रमुख त्योहार से पूर्व भुगतान की पहल से किसानों को बड़ी राहत मिली है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। जिला प्रशासन एवं कारखाना प्रबंधन ने किसानों के हित में इसी प्रकार निरंतर कार्य करते रहने का विश्वास दिलाया है।

भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना प्रबंधन ने शेयरधारक सदस्य किसानों एवं गैर-सदस्य गन्ना उत्पादकों से सर्वे के अनुरूप अधिकतम गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील की है। प्रबंधन ने इसे सहकारिता को मजबूत करने और किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने का साझा अवसर बताया है। विगत पेराई सत्र 2024-25 एवं वर्तमान पेराई सत्र 2025-26 में सर्वे अनुमान के अनुरूप गन्ना आपूर्ति नहीं हो पाने के कारण कारखाने की पेराई क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो सका, जिससे पेराई अवधि प्रभावित हुई। उन्होंने बताया कि पर्याप्त गन्ना आपूर्ति होने से पेराई अवधि बढ़ेगी, उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों को आगे भी समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

कारखाना प्रबंधन ने कारखाने की पंजीकृत उपविधियों के अंतर्गत जानकारी देते हुए बताया कि उपविधि धारा 07(02)(च) के अंतर्गत सदस्य किसानों के लिए अपने उत्पादित गन्ने की आपूर्ति कारखाने में करना अनिवार्य है। वहीं उपविधि धारा 09(क)(05) में यह प्रावधान है कि यदि कोई सदस्य लगातार सर्वे के अनुसार गन्ना आपूर्ति नहीं करता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि सहकारी संस्था की निरंतरता और किसानों के दीर्घकालिक हितों की रक्षा करना है।

किसानों के हित में सतत प्रयास

कारखाना प्रबंधन ने कहा कि भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना अपनी स्थापना से ही क्षेत्र के गन्ना किसानों की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति का सशक्त माध्यम रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों, जिला प्रशासन के मार्गदर्शन और किसानों के सहयोग से कारखाना निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। कारखाना द्वारा एफआरपी के अतिरिक्त रिकवरी की राशि, शासन द्वारा जारी बोनस राशि का भी भुगतान किया जाता है। शक्कर कारखाना द्वारा किसानों को शासन के सहयोग से रियायती दर पर शक्कर वितरण भी किया जाता है। गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों के लिए उन्नत बीज उपलब्ध कराया जाता है, गन्ना किसानों को गन्ना संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। किसानों के लिए कारखाना परिसर में सर्व सुविधा युक्त बलराम सदन का निर्माण किया गया है। कारखाना परिसर में श्रमिकों एवं किसान भाइयों के लिए केवल 5 रुपए में गरम भोजन के लिए कैंटीन शुरू की गई है। इस प्रकार भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना द्वारा अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जाता है।

अस्तित्व की रक्षा के लिए सामूहिक सहभागिता जरूरी

कारखाना प्रबंधन ने सभी शेयरधारक किसानों और अन्य गन्ना उत्पादकों से अपील की है कि वे सर्वे के अनुसार अधिक से अधिक गन्ना कारखाने में दें। प्रबंधन का कहना है कि अगर सभी किसान मिलकर सहयोग करेंगे तो पेराई का लक्ष्य आसानी से पूरा हो सकेगा और कारखाना मजबूत बना रहेगा। इससे सहकारी व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और क्षेत्र के गन्ना किसानों का भविष्य भी सुरक्षित और बेहतर होगा।

संपादकीय

लीडर वह होता है जो लोगों को अपनी बात समझा सके

हाल में बच्चों ने पीएम से पूछा था कि आप इतने सालों से देश संभाल रहे है,देश के लीडर हैं,आप नई पीढ़ी से एक लीडर के रूप में कौन से गुण की अपेक्षा रखते हैं।पीएम मोदी ने बच्चों को सरल भाषा में बताया था कि लीडर का मतलब चुनाव लड़ना,पार्टी बनाना,पार्टी में जाना,लच्छेदार भाषण करना नहीं होता। लीडरशिप के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप लोगों को अपनी बात समझा सको।अपनी बात लोगों पर थोपनी नहीं है,समझानी है,आप अपनी बात लोगों को तब ही समझा सकते हो जब आप उस बात को अच्छे से समझते हों। यदि आप जो कह रहे हैं,वह आप ही नहीं समझते हैं तो लोगों को नहीं समझा सकते। आप किसी बात को समझते हैं तो ही लोगों को समझा सकते हैं। अपनी बात लोगों को समझाने के लिए भाषा का सरल होना जरूरी है। जब भाषा सरल नहीं होती है तो लीडर क्या कह रहा है यह जनता को समझ में नहीं आता है।

कहने को तो राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर है, वह संसद में नेता प्रतिपक्ष भी हैं लेकिन पीएम मोदी के एक बार बच्चों को समझाने पर यह बात समझ में आ गई कि लीडर की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सरल हो और लोगों को समझ आ सके। राहुल गांधी के बारे में पता नहीं कितने लोगों ने कहा है कि उनकी भाषा ऐसी है कि वह क्या कहना चाहते हैं लोगों को समझ में नहीं आती है लेकिन न तो कांग्रेस नेता यह नेता मानते है कि राहुल गांधी की भाषा में कोई खराबी है और न ही राहुल गांधी को यह बात समझ में आती है वह लोगों से जो कुछ कहते हैं, वह लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है। वह लोगों को अपनी बात समझा क्यों नहीं पाते हैं। इससे राहुल गांधी को नुकसान हो रहा है और कांग्रेस को भी राजनीतिक रूप से नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ और जाते हैं, इसके कारण कई बार उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है,सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी है।

राहुल गांधी ने पहले तो बजट सत्र में बजट पर कुछ कहने की जगह एक किताब की कुछ लाइने पढ़ने को अड़े रहे।इससे संसद में कुछ दिन तक हंगामा होता रहा।अब जब राहुल गांधी ने बजट व भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते पर कुछ कहा है तो उसे लेकर भी बवाल हो गया है क्योंकि वह फिर ऐसा बहुत कुछ कह गए हैं कि उसे उचित नहीं माना जा रहा है। अपनी बात को कहने के लिए उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है,वह अपनी बात दूसरे शब्दों में कह सकते थे लेकिन कहा नही। उन्होंने कहा अंतरिम व्यापार समझौते में मोदी सरकार ने देश को बेच दिया है।भारत माता को बेच दिया है। अमरीका के सामने सरेंडर कर दिया है,यह बात तो वाकई तकर्संगत नहीं है कि कोई देश को कैसे बेच सकता है, कोई भारत माता को कैसे बेच सकता है। इससे तो कई तरह के सवाल लोगों के मन में उठ सकते हैं.क्या देश सरकार की निजी संपत्ति है, क्या भारत माता किसी सरकार की निजी संपत्ति है।

इसके बाद और भी सवाल पैदा होते हैं यदि किसी ने देश को बेच दिया है, भारत माता को बेच दिया है तो उसकी कीमत क्या है। बदले में कितने पैसे मिले हैं, देश व भारत माता को खरीदा किसने है। जो पैसा मिला है वह किसे दिया गया है इन सारे सवालों के जबाब राहुल गांधी को देना चाहिए। यदि वह इन सवालों के जवाब नहीं देते हैं तो माना यही जाएगा कि राहुल गांधी ने झुठ कहा है सरकार ने देश को बेच दिया है, सरकार ने भारत माता को बेच दिया है।यह माना जाएगा कि राहुलगांधी जो कुछ कहना चाहते है, वह कह नहीं पाए हैं और जो कहा है वह गलत है, झुठ है। राहुल गांधी अक्सर जो कुछ कहते है वह झुठ व गलत माना जाता है तो इसलिए कि उनकी भाषा लोगों को समझ में नहीं आती है और वह अपनी बात को सही साबित करने के लिए कोई सबूत आज तक नही दे पाए हैं।

राहुल गांधी कुछ कहते वक्त यह भूल जाते हैं कि वह जो कुछ कहने जा रहे है, वह कहेंगे तो कांग्रेस की बरसों सत्ता में रहने के दौरान हुई गलतियों को भी सामने लाया जाएगा और बताया जाएगा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं,वह काम तो कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए किया है। सेना अधिकारी की किताब के मामले में ऐसा हुआ.एक किताब के जवाब में कई किताबें सामने आ गई। देश बेचने के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को बताया कि विश्व व्यापार संगठन की 2013 को बाली में हुई बैठक में कांग्रेस ने हस्ताक्षर कर सरेंडर किया था। इससे हुआ क्या था, देश में किसानों के अनाज की सरकारी खरीद नहीं हो पाती थी, गरीब लोगों को राशन दुकान से अनाज नहीं मिल पाता था। पीएम मोदी इस गलती को सुधारा तब आज किसानों के धान की खरीदी हो रही है तथा गरीबों को राशन दुकानों से अनाज मिल रहा है।

पीड़ितों का शास्त्र न बन जाए उमर-शरजील की हिरासत

उमेश चतुर्वेदी

छह साल पहले राजधानी दिल्ली के उत्तरी-पूर्वी हिस्से के जाफराबाद और मौजपुर में हुए दंगों पर राजनीति थम नहीं रही है। राजनीति तब भी खूब हुई, जब 23 फरवरी 26 फरवरी 2020 के बीच हुए दंगों का घाव बिल्कुल हरा था। इस बार इन दंगों पर राजनीति की वजह पांच जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से आया एक आदेश है, जिसमें इन दंगों के पांच आरोपियों गुलफिशां फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहम और मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी गई है। इस आदेश को लेकर राजनीति ही नहीं हो रही, प्रकारांतर से देश की सबसे बड़ी अदालत भी निशाने पर है। सवीच्च अदालत ने इन दंगों के आरोपी शरजील इमाम उमर खालिद को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। इस फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया पर इन दोनों आरोपियों के पक्ष और सवीच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई। मनमोहन सिंह की सत्ता और कांग्रेस के आंख के तारे रहे जेएनयू के पूर्व छात्र रहे एक बड़े पत्रकार ने इन दोनों आरोपियों को देश का प्रखर बुद्धिजीवी बताते हुए उन्हें जमानत ना दिए जाने पर आश्चर्य जताया।

वामपंथी वैचारिकी की एक खासियत है। वह अपने पक्ष में अकादमिक तर्क गढ़ने में माहिर रही है। अपने लिहाज के तथ्यों को चुनकर उसके हिसाब से वह तर्क गढ़ने और अपने पक्ष में माहौल बनाने के साथ ही अपनी वैचारिकी के लोगों को पीड़ित दिखाने में वह हमेशा आगे रहती रही है। शरजील इमाम और उमर खालिद के पक्ष में वामपंथी वैचारिकी उसी तरह से उमड़ पड़ी है। वह दोनों के बारे में वह राय बनाने की भरपूर और प्रभावी कोशिश कर रही है कि दोनों दंगाई नहीं, दंगे के शातिर षड्यंत्रकारी नहीं, बल्कि वे प्रखर बुद्धिजीवी हैं। वामपंथी वैचारिकी यह साबित करने की भी कोशिश कर रही है कि दोनों चूंकि अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय से हैं, और चूंकि केंद्र में हिंदुत्ववादी सत्ता है। इसलिए अल्पसंख्यक बुद्धिजीवियों को दबाया और प्रताड़ित किया जा रहा है। वामपंथी वैचारिकी और उसकी बुद्धिजीवी जमात यह विमर्श खड़ा करने की कोशिश कर रही है कि हिंदुत्ववादी सत्ता के इशारे पर अदालत मुस्लिम समुदाय के निदोष बुद्धिजीवियों को बलि का बकरा बना रही है। यह विमर्श खड़ा करके वामपंथी वैचारिकी और उसकी बुद्धिजीवी जमात दरअसल दंगाईयों को पीड़ित के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रही है। दिलचस्प यह है कि उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत को नकारने के लिए जहां सवीच्च न्यायालय को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं बाकी पांच आरोपियों को जमानत दिए जाने के आदेश को जबरदस्ती नेपथ्य में धकेलने की कोशिश की जा रही है। दो लोगों को जमानत ना मिलने को, पांच लोगों को जमानत मिलने की प्रक्रिया के सामने पक्षपाती दिखाया जा रहा है। पांच आरोपियों को मिली जमानत को यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि ऐसा करके सवीच्च अदालत ने कोई एहसान नहीं किया है।

वामपंथी वैचारिकी के इस विमर्श का पूरा मकसद यह भुलाना है कि 2020 के दिल्ली दंगे हिंदू-मुस्लिम दंगे नहीं थे। इस विमर्श का लक्ष्य यह भी भुलाना है कि इन दंगों में अधिसंख्य हिंदू समुदाय के लोग मारे गए थे। इस विमर्श का यह भी मकसद है कि इन दंगों के दौरान आईबी के मासूम अधिकारी अंकित शर्मा की हुई हत्या को सामान्य अपराध दिखाने की कोशिश हो रही है। इन दंगों में आधिकारिक रूप से 53 लोग मारे गए थे। दंगा खत्म होने के बाद कई लाशें नाले में बहती मिलीं। जिस तरह उस दौरान दंगे के एक आरोपी आम आदमी पार्टी के तत्कालीन पार्षद ताहिर हुसैन के घर पत्थर, हथियार और बड़ी-सी गुलेल मिली, उससे तो यही साबित होता है कि दिल्ली के ये दंगे हिंदू समाज को सबक सिखाने की मुस्लिम समाज के कुछ दंगाइयों की कोशिश थी। इन दंगों की टाइमिंग को भी भुलाना आसान नहीं है। जब ये दंगे हुए थे, उसके कुछ ही दिन बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप का भारत दौरा हुआ था। इन दंगों के जरिए कोशिश यह भी की गई थी कि दंगा के षड्यंत्रकारियों का मकसद ट्रंप की भारत यात्रा को निरस्त कराना, भारतीय राज व्यवस्था को बदनाम करना और इसके जरिए भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाना था। इसमें किंचित वे कामयाब भी हुए।

शरजील इमाम और उमर खालिद के पक्ष में उठती आवाजों का प्रतिकार भी जरूरी है। इन आवाजों की पोल खोलना भी जरूरी है। राष्ट्रवादी धारा के प्रबुद्धजन वामपंथी विमर्श के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन जिस तरह कभी वामपंथी वैचारिकी के अगुआओं को देश की मौजूदा व्यवस्था में राजकीय तवज्जो मिल रहा है, उससे प्रखर राष्ट्रवादी वैचारिकी किंचित परेशान भी है और दुखी भी। इसलिए जैसा इस वामपंथी विमर्श का प्रतिकार होना चाहिए, उस स्तर का प्रतिकार नहीं हो पा रहा है। यह तो भला हो कि हिंदुत्ववादी मानस इन दिनों बेहद सचेत हो चुका है। निश्चित तौर पर इसकी वजह मुस्लिम तुष्टिकरण की हकीकत का सामने आना तो है ही, केंद्रीय सत्ता में मोदी की अगुआई में हिंदुत्वादी ताकतों का प्रभावी बनना भी है।

दिल्ली दंगों को लेकर नए विमर्श गढ़ने की कोशिशें होती रहेंगी। जरूरत यह है कि इसका लगातार उचित प्रतिकार तो होते ही रहे, हिंदुत्व विरोधी नैरेटिव के खिलाफ आक्रामक राष्ट्रवादी विमर्श लगातार उठता रहे। इसी अंदाज में होना यह चाहिए कि दिल्ली दंगों को लेकर बार-बार यह कहा जाना चाहिए कि ये हिंदुओं के खिलाफ खुराफाती और शांति विरोधी मुस्लिम सिरफिरों के सुनियोजित अपराध थे। जिसमें 53 लोगों की मौत हुई। इनमें ज्यादातर हिंदू थे। दो सौ से ज्यादा लोग घायल हुए। यह भी बताने की कोशिश होनी चाहिए कि घायलों में भी ज्यादातर हिंदू ही थे। इसकी भी बार-बार चर्चा होनी चाहिए कि इन दंगों में सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय की ही दुकानों और हिंदू समुदाय के ही मकानों को लक्ष्य बनाकर नुकसान पहुंचाया गया। यह भी बताने की कोशिश लगातार जारी रहनी चाहिए कि इन दंगों का एक मकसद तत्कालीन नागरिकता संबंधी कानून में संसद द्वारा किया गया संसोधन भी था। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जारी दुष्प्रचार भी था।

लगातार ऐसा जवाबी विमर्श खड़ा होता रहा तो मुस्लिम समुदाय के शांति विरोधी और अपराधी और दंगाई समर्थक वर्ग की मंशा का खुलासा करना आसान होगा। लगातार जारी ऐसे विमर्श की वजह से हिंदुत्व विरोधी ताकतें जहां एक्सपोज होंगी, वहीं उनके खिलाफ आम मानस उठ खड़ा होगा। अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने वाली राजनीतिक धाराएं भी इससे एक्सपोज होंगी। इस प्रक्रिया के लगातार जारी रहने के चलते एक दौर ऐसा भी आएगा, जब छद्म विमर्शकारों के सामने सच को पूरी हकीकत के साथ स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पडेगा।

फिलहाल यह जान लेना चाहिए कि जिन पांच आरोपियो को सवीच्च अदालत ने जमानत दी है, उन्हें दो-दो लाख के निजी मुचलके पर रिहा किया गया है। सवीच्च अदालत ने इन आरोपियों की जमानत मंजूर करते वक्त बारह कड़ी शर्तें लगाई हैं। अदालत ने कहा है कि ये आरोपी किसी रैली में हिस्सा नहीं ले सकते और पोस्टर नहीं बांट सकते। अदालत ने ताकीद की है कि वे किसी भी कीमत पर अपने खिलाफ चल रहे मामले को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। हालांकि जमानत पर बाहर आए ये पांचों आरोपी लगातार पाडकास्ट कर रहे हैं, समाचार माध्यमों को साक्षात्कार दे रहे हैं। इसके जरिए वे जेल जीवन की विद्रूपताओं को उजागर तो कर ही रहे हैं, राजव्यवस्था को पक्षपाती साबित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जमानत पाए आरोपियों के इन कार्यों का मकसद असल में हिंदुत्ववादी विचारधारा, भारतीय राज व्यवस्था और न्याय्व्यवस्था को कठघरे में खड़ा करना है। राष्ट्रवादी ताकतों को अगर इन ताकतों पर पार पाना है तो वामपंथी वैचारिकी के खिलाफ तार्किक हमला करना होगा, भावनात्मक नहीं।

प्रकाशन के इंतजार में नरावणे की किताब

सत्ता पक्ष के मुताबिक चूंकि किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है, इसलिए उसमें वर्णित मामलों का उल्लेख सदन में नहीं हो सकता। मगर किताब का प्रकाशन किसने रोक रखा है ? बेहतर होगा कि प्रकाशन की मंजूरी अविलंब दी जाए।

पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरावणे की किताब लगभग 21 महीनों से प्रकाशन के इंतजार में है, क्योंकि उसे केंद्र से हरी झंडी नहीं मिली है। अब उस किताब में वर्णित बातों को लेकर एक अंग्रेजी पत्रिका ने लंबी रिपोर्ट छापी है। उसमें शामिल एक प्रकरण का हवाला विपक्ष के नेता राहुल गांधी लोकसभा में देना चाहते थे। मगर सत्ता पक्ष की आपत्तियों के बीच स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं दी। बहरहाल, कांग्रेस ने उस पूरी रिपोर्ट को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाल कर उसे जनमत के बड़े हिस्से तक पहुंचा दिया है। इसके मुताबिक अगस्त 2020 में रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण कैलाश रेंज की चोटी पर भारतीय फौज के नियंत्रण के बाद चीन ने हमला करने की तैयारी की थी। जब टैंकों समेत चीनी सेना की टुकडि ?ां आगे बढ़ रही थीं, तब तत्कालीन सेनाध्यक्ष नरावणे ने बार-बार रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और विदेश मंत्री को फोन कर जवाबी कार्रवाई के लिए निर्देश मांगे।

मगर इस पर घंटों तक टाल-मटोल की गई। आखिरकार प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद राजनाथ सिंह ने उन्हें निर्देश दिया- जो उचित लगे, वह करें। स्पष्टतः ये प्रकरण वर्तमान सरकार की नेतृत्व क्षमता एवं संकल्प शक्ति को कठघरे में खड़ा करता है। सेना युद्ध संबंधी फौरी (टैक्टिल) फैसले ले सकती है, लेकिन ऑपरेशनल एवं रणनीतिक निर्णय लेने की स्थिति में सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व होता है। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल नरावणे के सामने कई कठिन प्रश्न थे। कोरोना के कारण देश अस्त-व्यस्त था, जिससे मोर्चों पर सहज सप्लाई को लेकर आशंकाएं थीं। फिर युद्ध फैलता, तो विदेश नीति एवं कूटनीति संबंधी उसके परिणामों का आकलन सरकार ही कर सकती थी। मगर उस कठिन घड़ी में केंद्र ने जिम्मेदारी सेनाध्यक्ष पर टाल दी। सत्ता पक्ष का कहना है कि चूंकि किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है, इसलिए उसमें वर्णित मामलों का उल्लेख सदन में नहीं हो सकता। मगर प्रश्न है कि किताब का प्रकाशन किसने रोक रखा है? सरकार के पास कुछ ढकने को नहीं है, तो बेहतर होगा कि वह तुरंत किताब प्रकाशन की मंजूरी दे, ताकि देश तत्कालीन सेनाध्यक्ष के अनुभव उनके ही शब्दों में जान सके।

शंकराचार्य मुद्दे पर सरकार का समर्थन

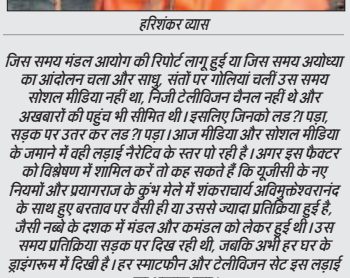

हरिशंकर व्यास

जिस समय मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई या जिस समय अयोध्या का आंदोलन चला और साधु, संतों पर गोलियां चलीं उस समय सोशल मीडिया नहीं था, निजी टेलीविजन चैनल नहीं थे और अखबारों की पहुंच भी सीमित थी। इसलिए जिनको लड?ा पड़ा, सड़क पर उतर कर लड ?ा पड़ा। आज मीडिया और सोशल मीडिया के जमाने में वही लड़ाई नैरेटिव के स्तर पो रही है। अगर इस फैक्टर को विश्लेषण में शामिल करें तो कह सकते हैं कि यूजीसी के नए नियमों और प्रयागराज के कुंभ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए बरताव पर वैसी ही या उससे ज्यादा प्रतिक्रिया हुई है, जैसी नब्बे के दशक में मंडल और कमंडल को लेकर हुई थी। उस समय प्रतिक्रिया सड़क पर दिख रही थी, जबकि अभी हर घर के ड्राइंगरूम में दिखी है। हर स्मार्टफोन और टेलीविजन सेट इस लड़ाई का अखाड़ा बना।

इन दोनों मुद्दों को लेकर वास्तविक यानी सड़क पर उतर कर भी लड़ाई हुई लेकिन ज्यादा बड़ी लड़ाई आभासी यानी वर्चुअल थी। उसको देखें तो कई बातें दिखती हैं। कई लोगों का मानना है कि यह सिर्फ संयोग है कि शंकराचार्य की घटना और यूजीसी के नियम एक ही समय में आए। वे इसको भी संयोग मान रहे हैं कि माघ मेले में शंकराचार्य पालकी लेकर गए, जिस पर टकराव हो गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी आदत के मुताबिक अड़ गए, जिससे विवाद आगे बढ़ गया। ऐसे ही यूजीसी के नियम भी संयोग हैं। जान बूझकर जारी नहीं किए गए। यूजीसी के नियम पर सुप्रीम कोर्ट की रोक और शंकराचार्य को मना कर पूणिमां के दिन स्नान के लिए माघ मेले में लाने की खबर से इन घटनाओं को संयोग मानने वाले संतुष्ट हुए हैं।

एक दूसरी धारणा इनको प्रयोग मानने की है। माना जा रहा है कि ब्राह्मणवादी हिंदुत्व को कमजोर करने और बहुजन आधारित हिंदुत्व को मजबूत करने के प्रयोग के तौर पर ये दोनों काम हुए हैं। हिंदुत्व का चेहरा तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ है ही। अब इन्होंने कुछ ऐसा किया है, जिससे इधर उधर भाग रही पिछड़े, दलित और आदिवासियों को इनके चेहरे के ईर्द गिर्द गोलबंद किया जाए। अगर्डा को निशाना बना कर यह काम किया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा मान रही है कि अगड़ी जातियों के लोग मजबूरी में उसको वोट करेंगे इसलिए उनकी ज्यादा परवाह करने की जरुरत नहीं है। ध्यान रहे शंकराचार्य का पद ही ऐसा है, जो वेदपाठी, संस्कृत जानने वाले ब्राह्मण के लिए होता है।

शंकराचार्य ही शंकराचार्य नियुक्त करते हैं। बाकी कथावाचक कोई भी बन सकता है और महामंडलेश्वर का क्या है वह तो हिंदी सिनेमा की एक अभिनेत्री भी बन गई थी, जिसको अब हटाए जाने की खबर है। तभी चारों शंकराचार्यों के अलावा जितने भी कथावाचक, महामंडलेश्वर, योग गुरू, मठ, साधु, संत, मठ व धाम बनाने वाले लोग हैं उनमें से ज्यादातर ने शंकराचार्य वाले मुद्दे पर सरकार का समर्थन किया। वे शंकराचार्य को ही दोषी ठहराते रहे। रामदेव से लेकर रामभद्राचार्य तक ज्यादातर ने शंकराचार्य की ही गलती निकाली। इसका कारण यह है कि शंकराचार्यों को सत्ता के संरक्षण की जरुरत नहीं होती है, जबकि बाकी सब को सत्ता के संरक्षण में फलना फूलना होता है। वे हिंदुओं को धर्म या अध्यात्म की ओर नहीं ले जाते हैं, बल्कि भक्त बना कर भाजपा के समर्थन की ओर ले जाते हैं।

अंग्रेज के जमाने में भी लाट साहेब थे और अब भी लाट साहेब ही रहेंगे

अजीत द्विवेदी

प्रदेशों की राजधानियों में अंग्रेजों के जमाने में बने और कई कई एकड़ में फैले विशाल भवनों को, जहां राज्यपाल रहते हैं, राजभवन कहा जाए या लोकभवन क्या फर्क पड़ता है ? लोकभवन नाम रख देने से न तो उसमें रहने वालों की उपयोगिता बढ़ जाएगी और न उनका एटीट्यूड बदल जाएगा। वे अंग्रेज के जमाने में भी लाट साहेब थे और अब भी लाट साहेब ही रहेंगे। सजावटी और बिना मतलब का पद होने के बावजूद उनको वह प्रोटोकॉल मिलेगा, जो राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री को मिलता है। वे कई एकड़ में फैले भवनों में रहेंगे, सैकड़ों कमर्चारी उनकी सेवा करेंगे, उनको भारी भरकम सुरक्षा मिलेगी और वे बड़ी गाड़ियों में ढेर सारी गाड़ियों के काफिले के साथ सड़क पर निकलेंगे। इतना ही नहीं केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं के अलावा उनके लौह द्वार पर न तो कोई और दस्तक दे सकता है और न उनके दस्तक से आम लोगों के लिए लौह द्वार खुलता है।

पहले अपवाद के तौर पर होता था लेकिन अब यह नियम हो गया है कि लोकभवन में रहने वाला केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की आंख से चीजों को देखेगा और उसकी कान से ही चीजों को सुनेगा। साथ ही यह भी अब मेनस्ट्रीम हो गया है कि वह संविधान से ज्यादा राजनीति को महत्व देगा। अगर राज्य में भाजपा विरोधी पार्टी की सरकार है तो लोकभवन में रहने वाले उसका जीना दूभर किए रहेंगे। उस राज्य में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना कानून व्यवस्था के लिए खतरा दिखाई पड़ेगी और उसमें दखल देकर उसका मुद्दा बनाया जाएगा। उन राज्यों की विधानसभाओं से पास किए गए विधेयक अनावश्यक तरीके से रोके जाएंगे। पहले जो एक झीना सा परदा होता था अब उसे भी उतार दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि राजभवन को लोकभवन बनाने का यह अनिवार्य नतीजा है कि उसमें रहने वाले लोग लोकनेता की तरह व्यवहार करेंगे और केंद्र में सत्तारूढ़ दल की आलोचना नहीं बरदाश्त करेंगे। इसलिए वे राज्य सरकारों की ओर से तैयार किए गए अभिभाषण नहीं पढ़ेंगे। इससे पहले कभी भी राज्यपालों की ऐसी राजनीति देखने को नहीं मिली थी।

एक के बाद एक तीन राज्यों में यह राजनीति देखने को मिली है। तमिलनाडु का नाम बदलने तक का प्रयास कर चुके राज्यपाल आरएन रवि वहां की विधानसभा की कार्यवाही का नियम बदलना चाहते हैं। तमिलनाडु विधानसभा के सत्र की कार्यवाही तमिल के प्रदेश गान से शुरू होती है और समापन राष्ट्रगान से होता है। पिछले चार साल से साल के पहले सत्र में राज्यपाल अभिभाषण नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि कार्यवाही की शुरुआत राष्ट्रगान से हो। इस साल भी इसी नाम पर वे अभिभाषण पढ़े बगैर वापस चले गए।लेकिन अभिभाषण नहीं पढ़न का एक कारण यह भी है कि तमिलनाडु सरकार के तैयार किए गए अभिभाषण में केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत सारी बातें थीं। सो, केंद्र सरकार के खिलाफ कोई बात है तो वह कैसे राज्यपाल पढ़ सकते हैं!

केरल में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यही काम किया है। उन्होंने अभिभाषण पढ़ा लेकिन पैराग्राफ नंबर 12 का शुरुआती हिस्सा छोड़ दिया, जिसमें केंद्र सरकार के ऊपर संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करने और राज्य को आर्थिक व अन्य रूप से परेशान करने की बात थी। उन्होंने पैराग्राफ 15 का अंतिम हिस्सा भी नहीं पढ़ा क्योंकि उसमें राज्य विधानसभा से पास विधेयक बेवजह रोके जाने का जिक्र था।

ध्यान रहे पिछले और मौजूदा राज्यपाल दोनों ने कई विधेयक महीनों तक रोके रखा। तीसरे राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। उन्होंने कर्नाटक विधानमंडल के इस साल के पहले सत्र की साझा कार्यवाही में अभिभाषण पढ़ने से इनकार कर दिया। राज्य के कानून व संसदीय कार्यमंत्री का कहना है कि 11 पैराग्राफ्स को लेकर राज्यपाल को आपत्ति थी। उन्होंने इन्हें हटाने के लिए कह दिया। सोचें, इससे पहले कब अभिभाषण को लेकर इस तरह की आपत्ति राज्यपाल जताते थे? यह न्यू इंडिया की पिछले 12 साल की परिघटना है कि राज्यपाल राज्य सरकार की ओर से तैयार अभिभाषण में नुक्स निकालेंगे, उसे पढ़ने से मना कर कर देंगे या मनमाने तरीके से कुछ हिस्सा पढ़ेंगे और कुछ छोड़ देंगे।

अब तक यह परंपरा रही है कि राज्यपाल राज्य सरकार की ओर से तैयार किए गए अभिभाषण को शब्दशः पढ़ेंगे। लेकिन इन दिनों राज्यपालों को भाजपा विरोधी पार्टियों की सरकारों की ओर से तैयार किए गए अभिभाषण पढ़ने में बहुत कष्ट हो रहा है क्योंकि उसमें खुद राज्यपालों की भूमिका की आलोचना होती है और केंद्र सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए जाते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल कार्यालय ने उनके अभिभाषण नहीं पढ़ने का एक कारण यह भी बताया है कि उसमें 'आधे अधूरे दावे और गुमराह करने वाली बातें हैं थीं। ध्यान रहे अभिभाषण चाहे राष्ट्रपति का हो या राज्यपालों का उसमें सरकारें अपनी उपलब्धियां ही बताती हैं वो सही हैं या गलत यह जांच करना राष्ट्रपति या राज्यपाल का काम नहीं होता है। पहले कोई भी इनकी जांच नहीं करता था। लंबे समय तक देश में कांग्रेस की सरकार रही लेकिन यह अपवाद के लिए ही कहीं देखने को मिला होगा कि राज्यों में कांग्रेस विरोधी सरकारों की ओर से तैयार अभिभाषण पढ़ने से किसी राज्यपाल ने इनकार किया हो या उसमें सुधार किया हो।

लेकिन अब यह इतनी सामान्य परिघटना हो गई है कि भाजपा विरोधी शासन वाले राज्यों का हर राज्यपाल अभिभाषण में सुधार करवा रहा है या पढ़ने से इनकार कर रहा है या अधूरा पढ़ रहा है। विधानसभा से पास विधेयकों को लंबे समय तक रोके रखना भी एक सामान्य परिघटना हो गई है और कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार के कामकाज में अड़ंगेबाजी या उसकी आलोचना भी एकदम सामान्य बात हो गई है। इससे एक गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। आगे जब केंद्र की सरकार बदली तब भी यह परंपरा जारी रहेगी और उससे राज्यों में स्थायी टकराव की संभावना बनी रहेगी। इसलिए इसे रोका जावा चाहिए। ध्यान रहे देश में लंबे समय से इस बात की चर्चा होती रही है कि राज्यपाल का पद जरूरी है या नहीं। इसे चेक एंड बैलेंस के लिए बनाया गया था लेकिन राज्यपाल चेक एंड बैलेंस का काम सिर्फ उन्हीं प्रदेशों में करते हैं, जहां केंद्र सरकार की विरोधी पार्टी की सरकार होती है।

आजादी के बाद 78 साल का अनुभव यह बताता है कि राज्यपाल का पद होने से राज्य के कामकाज पर कोई गुणात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। यह सिर्फ टकराव बढ़ाने के काम आता है। वैसे भी भारत में शासन की जो प्रणाली अपनाई गई है उसमें चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव बनाने या उसे काम करने से रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस बात पर सहमति रही है कि राज्यपालों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए और उन्हें राजकाज में दखल से रोकना चाहिए। फिर भी अगर अभी राज्यपाल का पद नहीं समाप्त किया जाता है तो कम से कम अभिभाषण की प्रथा खत्म कर देनी चाहिए।

यह एक तमाशा है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। देश के एक विद्वान राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने इसके लिए बहुत प्रयास किया था। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्रियों राजीव गांधी और चंद्रशेखर दोनों को कई बार कहा कि संविधान के अनुच्छेद 87 और 176 में संशोधन करके राष्ट्रपति और राज्यपालों के अभिभाषण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। आर वेंकटरमन के प्रयासों के 35 साल बाद अब यह अनिवार्य हो गया है कि ये दोनों अनुच्छेद बदले जाएं और अभिभाषण की व्यवस्था समाप्त हो।

खास खबर

शराबखोरी को बढ़ावा देने नई-नई शराब दुकाने खोल रही है सरकार

रायपुर /बार-बार बदले जा रहे आबकारी नीति और नए-नए शराब दुकान खोलने पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि एक तरफ साय सरकार लगातार नई शराब दुकानें खोल रही है, दूसरी तरफ इस सरकार में पुलिस ही ड्रग्स की तस्करी कर रही है। इस सरकार की नियत और जमीनी हकीकत बिल्कुल साफ है, मुनाफाखोरी के लालच में छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाया जा रहा है। सत्ता के संरक्षण में नकली शराब, अवैध शराब, गुणवत्ताहीन शराब के साथ ही सूखे नशे का कारोबार पूरे प्रदेश में फल-फूल रहा है, गांजा, नशीली दवाएं और नशे के पाउडर सीमा पार से लाकर छत्तीसगढ़ में बेचे जा रहे हैं, सरकार खुद ही नए-नए शराब दुकान खोल कर शराबखोरी को बढ़ावा दे रही है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि इस जनविरोधी सरकार ने निर्णय लिया है कि अब 1 अप्रैल से फाइबर की बोतल में शराब मिलेगी। साथ ही 35 नई दुकानों के शटर भी खोले जाएंगे। शराब की काली कमाई के लालच में भाजपा की सरकार ने पिछले दो वर्षों में आधा दर्जन बार आबकारी नीति में परिवर्तन किया है। पूर्व में संचालित लगभग 700 दुकानों में कंपोजिट व्यवस्था लागू करके अंग्रेजी में देसी और देसी शराब दुकानों में अंग्रेजी शराब भी बेचने का निर्णय लिया अर्थात पुरानी दुकानों की क्षमता दुगनी की, यही नहीं इस सरकार ने पिछले साल 67 नई शराब दुकानें खोले, जिसका जमकर विरोध हुआ, अब नई नीति में 35 और शराब दुकान खोले जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना : 115 दूल्हों की एक साथ निकली बारात, पैदल मार्च बना आकर्षण

नई दृष्टिबिंदु / खैरागढ़

छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत जिला स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम का भव्य आयोजन छुईखदान के केकती बाड़ी मैदान में किया गया। इस अवसर पर 115 जोड़े विधिवत वैवाहिक बंधन में बंधे, जिससे पूरा छुईखदान क्षेत्र उल्लास और विवाहोत्सव के रंग में रंगा नजर आया।

कार्यक्रम की सबसे विशेष और आकर्षक झलक तब देखने को मिली, जब 115 दूल्हों की सामूहिक बारात बैंड-बाजे के साथ लगभग एक किलोमीटर पैदल मार्च करते हुए विवाह स्थल तक पहुंची। एक ही बैंड की धुन पर थिरकते हजारों बारातियों ने नगर को उत्सवमय बना दिया। मार्ग में नागरिकों ने पुष्पवर्षा कर बारात का स्वागत किया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बारातियों का भव्य स्वागत किया गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग बना 'घराती'

इस सामूहिक विवाह आयोजन में महिला एवं बाल विकास विभाग ने घराती की भूमिका निभाई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दुल्हनों की सहेलियां बनीं और विवाह की सभी पारंपरिक रस्मों में सक्रिय सहभागिता निभाई। खैरागढ़ एवं छुईखदान विकासखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा हल्दी, स्वागत एवं अन्य वैवाहिक रस्में संपन्न कराई गईं, जिससे आयोजन में आत्मीयता और सामाजिक सहभागिता का सुंदर उदाहरण देखने को मिला।

दहेज-विहीन विवाह को मिला बढ़ावा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नवविवाहित जोड़ों को चेक के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की गई तथा आवश्यक घरेलू सामग्री भी भेंट स्वरूप दी गई। इससे दहेज-विहीन विवाह की परंपरा को प्रोत्साहन मिला और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सशक्त सहयोग प्राप्त हुआ।

जनप्रतिनिधियों ने दी बधाई

कार्यक्रम में विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका खम्मन ताम्रकार जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, कलेक्टर इंद्रजीत कुमार चंद्रवाल सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा ने नवविवाहित जोड़ों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका खम्मन ताम्रकार ने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए संबल है और बेटियों के सम्मान को बढ़ावा देती है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब माता-पिता के लिए बड़ा सहारा है।

कलेक्टर इंद्रजीत कुमार चंद्रवाल ने बताया कि शासन द्वारा प्रत्येक कन्या के लिए 35,000 उपहार सामग्री हेतु डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि दी जा रही है। कार्यक्रम के सफल संचालन में ठरर रानी दुर्गा अवंती बाई कॉलेज छुईखदान के एनएसएस वॉलिंटियर्स का सहयोग अतुलनीय रहा। वॉलिंटियर्स ने बारात व्यवस्था, अतिथियों के मार्गदर्शन, मंच संचालन सहयोग एवं अनुशासन बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसकी सभी ने भूरी-भूरी प्रशंसा की।

सामूहिक विवाह आयोजन से पूरे छुईखदान क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल रहा। नागरिकों ने शासन की इस सामाजिक पहल की सराहना करते हुए नवदंपतियों को शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ प्रेम कुमार पटेल, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी पी. आर. खूंटेल, जनपद पंचायत छुईखदान की सीईओ केशवरी देवांगन, परियोजना अधिकारी रंजना श्रीवास्तव, सुनील बंजारे, जनपद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच तथा वर-वधु के परिजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

आदिवासियों पर प्राण घातक हमला -आपराधिक प्रकरण दर्ज है उसे राजनीतिक बताकर वापस लेना पीड़ितों के साथ अन्याय

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

बालोद जिला में भाजपा नेताओं पर दर्ज आपराधिक प्रकरण को राजनीतिक बताकर वापस लिए जाने को पीड़ितों के साथ अन्याय करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार अपने नेताओं पर दर्ज आपराधिक प्रकरण को राजनीतिक बताकर वापस ले रही है, ये पीड़ित आदिवासी वर्ग के साथ अन्याय है। प्रकरण वापस होने की खबर के बाद आक्रोशित आदिवासी समाज ने बालोद कलेक्टर का घेराव कर विरोध जताया, न्याय की मांग की।

1 मई 2022 को आदिवासी समाज जो अपनी परम्परा का निर्वहन कर रहे उन पर भाजपा नेताओं ने समूह बनाकर हमला किया था। आरोपियों पर तुएगोंदी गांव के आदिवासी वर्ग के साथ तलवार, चाकू, लाठी लेकर मारपीट करने, जान से मारने, गम्भीर चोट पहुँचाने, हत्या का प्रयास करने का गम्भीर आरोप है, जिस पर बालोद जिला के थाना मुंगघुवा में दर्ज अपराध क्रमांक 16/22 प्रकरण क्रमांक 58/23 जिस पर धारा 307, 120बी, 147, 148, 149, 294, 323, 506, 25, 27, आर्म्स एक्ट, एवं 3(2)(ट) एससी/एस टी एक्ट के तहत मामला दर्ज है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आदिवासी वर्ग के साथ अत्याचार करने वाले अपराधी किस्म के लोगों को जिसे न्यायालय सजा देगी। ऐसे में सरकार इस प्रकरण को राजनीतिक प्रकरण घोषित कर कैसे वापस ले सकती है, ये पीड़ितों के साथ अन्याय है। आपराधिक प्रकरण वापसी की सूचना मिलने से आक्रोशित तुएगोंदी गांव के पीड़ित आदिवासी समाज के लोगों ने बालोद कलेक्टर कार्यालय पहुँचकर विरोध जताया। आपराधिक प्रकरण के तहत कार्यवाही की मांग की।

मां पाताल भैरवी सिद्धपीठ में महाशिवरात्रि पर्व पर द्वादश ज्योर्तिलिंगों का रुद्राभिषेक 15 को

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

मानव सेवा एवं जनकल्याण के लिए अंचल सहित देशभर में पहचान बना चुकी बर्फानी सेवाश्रम समिति द्वारा हिन्दू पंचांग के अनुसार 15फरवरी रविवार को भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर मां पाताल भैरवी सिद्धपीठ स्थित विश्व के सबसे बड़े ज्योर्तिलिंग में विराजमान द्वादश ज्योर्तिलिंगों के साथ विशाल स्फटिक के पातालेश्वर महादेव व पारे के भव्य पारेशवर ज्योतिर्लिंग का महारुद्रा अभिषेक रात्रि 10 बजे से आयोजित किया गया है। जिसमें श्रद्धालुगण भी हिस्सा ले सकते हैं।

संस्था के सचिव गणेश प्रसाद शर्मा गन्नू ने बताया कि अखिल भारतीय चर्तुः सम्प्रदाय के पूर्व श्रीमहंत श्रीश्री 1011 योगाधिराज ब्रम्हर्षि बर्फानी दादा जी के आशीर्वाद व मार्गदर्शन से नगर में बर्फानी आश्रम स्थित मां पाताल भैरवी राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी दस महाविद्या द्वादश ज्योर्तिलिंग शिव शक्ति सिद्धपीठ स्थापित किया गया है। जिसमें वर्षभर जनकल्याण व मानस सेवा के साथ ही समय समय पर विभिन्न पर्वो पर

धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया जाता है। इसी कड़ी पर इस वर्ष भी 15 फरवरी रविवार को पड़ने वाली महाशिवरात्रि के अवसर पर रात्रि 10 बजे से विश्व शांति व जनकल्याण के लिए सिद्धपीठ स्थित विशाल 108 फीट ऊंचे शिवलिंग के प्रथम तल पर विराजमान दुर्लभ स्फटिक के आकर्षक पातालेश्वर महादेव व तृतीय तल पर विशालकाय भोलेनाथ शिवशंकर के साथ विराजमान द्वादश ज्योर्तिलिंगों देश के अद्वितीय पारे के पारेशवर महादेव का महारुद्रा अभिषेक आयोजित है। भगवान भोलेनाथ का यह रुद्राभिषेक दूध, दही, पंचामृत, शुद्ध घी, अष्टगंध, शहद, गंगाजल, सुगंधित इत्र एवं शुद्ध जल से विद्वान पंडितों के मंत्रोच्चार के मध्य किया जाएगा। जिसमें भगवान भोलेनाथ के द्वादश ज्योर्तिलिंगों के विशेष श्रृंगार, हवन एवं महा आरती भी आयोजित की जाएगी। इसके अलावा सिद्धपीठ प्रातः ब्रम्हमुहूर्त से अंचल सहित देशभर से आनेवाले शिवभक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। जिसमें भगवान भोलेनाथ के भक्त पूजा, अर्चना, अभिषेक कर सकेंगे। संस्था द्वारा चौथे पहर रात्रि में अपने सदस्यों व श्रद्धालुओं के लिए महारुद्राभिषेक का आयोजन करेगी। संस्था ने

इसकी तैयारियों को लेकर पिछले दिनों संस्था के अध्यक्ष राजेश मारु, उपाध्यक्ष दीपक जोशी, सचिव गणेश प्रसाद शर्मा ह्यगन्नूह्ण, कोषाध्यक्ष नीलम जैन, महंत गोविंद दास, महेन्द्र लुनिया, , सूरज जोशी, आलोक जोशी, कुलबीर सिंह छाबड़ा, योगेन्द्र पांडे, बलविंदर सिंह भाटिया, मनीष परमार, संजय खंडेलवाल, दामोदर अग्रवाल के अलावा अन्य सदस्यगण लगे हुए हैं। संस्था द्वारा आम श्रद्धालुओं व गुरु परिवार के सदस्यों से भगवान भोलेनाथ के महारुद्राभिषेक व अनुष्ठान में सम्मिलित होने की अपेक्षा की गई है।

इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में पुरालिपि और पुरालेख अध्ययन विषय पर सात दिवसीय कायर्शाला का होगा आयोजन

नई दृष्टिबिंदु / खैरागढ़

इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के रवीन्द्र बहादुर संग्रहालय में कुलपति प्रो.(डॉ.) लवली शर्मा के संरक्षण में तथा संस्कृति विभाग, छ.ग. शासन के सहयोग से सात दिवसीय कायर्शाला का आयोजन किया गया है। उक्त कायर्शाला के ब्रोशर का विमोचन कुलपति प्रो (डॉ)लवली शर्मा के द्वारा किया गया। इस दौरान अधिष्ठाता कला संकाय प्रो. राजन यादव व संग्रहालय अध्यक्ष डॉ. आशुतोष चौरे उपस्थित रहे।

पुरालिपि एवं पुरालेख अध्ययन विषय पर सोमवार 16 से रविवार 22 फरवरी 2026 तक आयोजित सात दिवसीय कायर्शाला के निदेशक प्रो. (डॉ.) राजन यादव अधिष्ठाता कला संकाय हैं। विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉ. टी.एस. रविशंकर भूतपूर्व निदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मैसूर उपस्थित होंगे। परामर्श मंडल में कुलसचिव, वित्त अधिकारी हैं तथा कार्यक्रम के संयोजक डॉ. आशुतोष चौरे संग्रहालय अध्यक्ष हैं। आयोजन समिति में सह-प्राध्यापक हिन्दी विभाग डॉ. देवमाईत मिंज, सहायक प्राध्यापकगण डॉ. पूणिर्मा केलकर संस्कृत विभाग, डॉ. रविनारायण गुप्ता ग्राफिक्स विभाग, डॉ. छगेन्द्र उसेंडी मूर्तिकला विभाग, कपिल सिंह वर्मा कला का इतिहास विभाग, डॉ. कौस्तुभ रंजन अंग्रेजी विभाग, संदीप किंडो चित्रकला विभाग, डॉ. प्रबोध गुप्ता प्रभारी कम्प्यूटर केन्द्र, डॉ. अजय पाण्डे योग अनुदेशक व प्रखर शरण सिंह म्यूजियम गाइड हैं। यह कायर्शाला शिक्षकों, इतिहासकारों, भाषाविदों एवं विद्यार्थियों के लिये बहु उपयोगी सिद्ध होगा। इस कायर्शाला में लगभग 2500 वर्ष पूर्व से लेकर 12वीं शती ईस्वी तक की भाषा एवं लिपियों को सीखना अपने आप में गौरव का विषय है। कायर्शाला के संबंध में अधिक जानकारी हेतु डॉ. आशुतोष चौरे संयोजक व प्रखर शरण सिंह समिति सदस्य से संपर्क कर सकते हैं।

मोदी की गारंटी निकली झूठी, किसानों को नहीं मिला एक मुश्त 3100 रु. क्विंटल धान की कीमत, दो किस्तों में दे रहे राशि

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

12 फरवरी 2026। किसानों को धान की कीमत 3100 रु प्रति क्विंटल एकमुश्त देने की गारंटी को झूठा करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा भाजपा सरकार ने किसानों को धोखा दिया है। किसानों को मोदी की गारंटी थी कि धान बेचते ही 3100 रु. प्रति क्विंटल की दर से धान बेचते ही पंचायत भवन में नगद भुगतान किया जायेगा, जो बीते दो साल में पूरा नही हुआ है। किसानों के लिए मोदी गारंटी झूठा साबित हो गया। भाजपा अपने सबसे बड़े नेता की किसानों को दी गई गांरटी को तोड़ दिया।

कांग्रेस ने पहले ही कहा था धान बेचने वाले किसानों को 3100 रु. की दर से भुगतान नहीं हो रहा है। आज आरोप सच साबित हुआ है।

जब भाजपा सरकार समर्थन मूल्य में धान खरीदी के बाद 3100 रु. की बकाया राशि होली त्यौहार में देने की घोषणा की है। भाजपा की कथनी और करनी में यही अंतर है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी की गारंटी थी सभी किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल की धान खरीदी जायेगी, लेकिन चालू खरीफ सीजन में किसान धान बेचने परेशान रहे है। अभी भी 7 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से लगभग 23 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी नही की गई। 16 लाख से अधिक किसानों का 5 लाख 50 हजार करीब रकबा कटौती कर प्रति एकड़ 21 किवंटल धान की खरीदी नही की गई।

किसानों धान का बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य 186 रु. प्रति क्विंटल नही दिया जा रहा है। जिससे किसानों को लगभग 7 हजार करोड़ का आर्थिक नुकसान हो रहा है। पूरी तरह से भाजपा सरकार किसानों को नुकसान पहुंचा रही है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि किसानों को 3286 रु. प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाये। जिन किसानों ने धान नही बेचा उनकी धान की खरीदी की जाये।

श्री रूख्खड़ स्वामी महोत्सव, नमर्दा कुंड से पवित्र जल लेकर निकली बाइक रैली

नई दृष्टिबिंदु / खैरागढ़

श्री रूख्खड़ स्वामी महोत्सव 2026 के शुभारंभ अवसर पर मंगलवार को आस्था, अनुशासन और सनातन परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। खैराझनमर्दा कुंड से पवित्र जल लेकर निकली भव्य बाइक रैली ने पूरे नगर को भक्तिमय वातावरण में रंग दिया। 150 से अधिक बाइकों और कई कारों के साथ श्रद्धालुओं का यह जत्था जब नगर में प्रविष्ट हुआ, तो हर मार्ग पर धर्मध्वज और जयघोष गूंज उठे।

सुबह से ही खैरा, नमर्दा कुंड और गंड़ई क्षेत्र के श्रद्धालु नमर्दा कुंड पर एकत्र हुए। विधिवत पूजा-अचर्ना के बाद कुंड से पवित्र जल लिया गया और भगवा ध्वजों के साथ बाइक रैली का शुभारंभ हुआ। यह रैली न केवल एक यात्रा थी, बल्कि क्षेत्रीय एकता, धर्म के प्रति समर्पण और सामूहिक साधना का प्रतीक भी बनी।

साईं मंदिर पर हुआ भव्य स्वागत

बाइक रैली जैसे ही नगर सीमा में प्रवेश कर साईं मंदिर पहुंची, वहां स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा और जयघोष के साथ रैली का स्वागत किया। यहीं पर हनुमान भगवान का रुद्राभिषेक एवं महामृत्युंजय मंत्र का पाठ संपन्न हुआ। इन वैदिक अनुष्ठानों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ।

उमड़ा जनसैलाब

साईं मंदिर से रैली नगर भ्रमण पर निकली। बस स्टैंड, ईतवारी बाजार, बख्शी मार्ग, गोलबाजार, मस्जिद चौक और जय स्तंभ चौक होते हुए रैली मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंची। मार्ग में जगह-जगह नागरिकों ने पुष्पांजलि अर्पित कर रैली का अभिनंदन किया। नगरवासियों ने इसे ऐतिहासिक और अनुकरणीय आयोजन बताया।

मां दंतेश्वरी मंदिर से निकली कलश यात्रा

मां दंतेश्वरी मंदिर में पहले से ही महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में कलश यात्रा के लिए तैयार थीं। जैसे ही बाइक रैली मंदिर परिसर पहुंची, नमर्दा कुंड से लाए गए पवित्र जल को कलशों में स्थापित कर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। बाइक से आए श्रद्धालु भी कलश यात्रा में पैदल शामिल हुए और भगवा ध्वजों के साथ जयघोष करते हुए आगे बढ़े।

अस्पताल चौक से रूख्खड़ स्वामी मंदिर तक पदयात्रा

कलश यात्रा मां दंतेश्वरी मंदिर से प्रारंभ होकर अस्पताल चौक होते हुए श्री रूख्खड़ स्वामी मंदिर परिसर पहुंची। मंदिर पहुंचते ही विधिवत पूजन के साथ कलश यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई और वातावरण हर-हर महादेव व जय बजरंगबली के नारों से गूंजता रहा।

श्रद्धालुओं के लिए भोजन व प्रसादी की व्यवस्था

यात्रा के समापन के बाद सभी श्रद्धालुओं के लिए सामूहिक भोजन की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही प्रसादी वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सहभागिता निभाई। आयोजकों की सुव्यवस्थित व्यवस्था और सेवा भाव की सर्वत्र सराहना की गई।

आस्था, संस्कृति और परंपरा का संगमः रुखड़ स्वामी महोत्सव में गंगा आरती आयोजकों का भव्य सम्मान समारोह

श्री रुखड़ स्वामी महोत्सव के शुभ अवसर पर आस्था, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां कार्तिक पूर्णिमा पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली गंगा आरती की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले आयोजकों और धर्म ध्वजा वाहकों का भव्य सम्मान किया गया। कार्यक्रम में गंगा आरती के संयोजक डॉ. अरुण भारद्वाज सहित महादेव मंदिर ट्रस्ट समिति के सभी सदस्यों को शॉल, श्रीफल और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। महोत्सव में उपस्थित श्रद्धालुओं और गणमान्य नागरिकों ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर हर वर्ष आयोजित होने वाली गंगा आरती क्षेत्र की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। हरिद्वार की तर्ज पर आयोजित इस आरती ने न केवल धार्मिक वातावरण को मजबूत किया है,बल्कि युवाओं में भी आध्यात्मिक चेतना और परंपराओं के प्रति जुड़ाव बढ़ाने का कार्य किया है। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन समाज में आपसी सौहार्द, एकता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। समिति के कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने भविष्य में भी इस परंपरा को और अधिक भव्य रूप में आगे बढ़ाने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए समाज सेवा और धार्मिक गतिविधियों को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया। महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे, जिससे पूरा वातावरण भक्ति और उत्साह से सराबोर रहा।

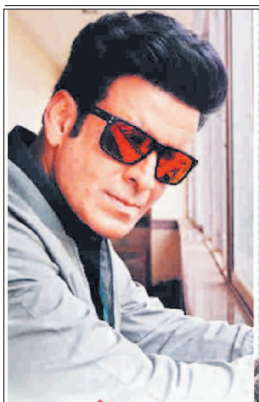

घूसखोर पंडत विवाद पर मनोज बाजपेयी ने तोड़ी चुप्पी

नेटफ्लिक्स की आगामी वेब सीरीज 'घूसखोर पंडत' रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। विवाद की वजह इसका टाइटल है, जिसे लेकर ब्राह्मण समुदाय के कुछ वर्गों ने आपत्ति जताई है। मामला इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका, लखनऊ में एफआईआर और देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन तक पहुंच गया। इसी बीच अब इस पूरे विवाद पर सीरीज के मुख्य अभिनेता मनोज बाजपेयी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने फिल्ममेकर नीरज पांडे के आधिकारिक बयान को शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखी है। मनोज बाजपेयी ने अपने पोस्ट में सबसे पहले लोगों की भावनाओं को सम्मान देने की बात कही। उन्होंने लिखा, 'लोगों ने जो भावनाएं और चिंताएं साझा की हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और उन्हें गंभीरता से लेता हूं। जब आप किसी ऐसी चीज का हिस्सा होते हैं जिससे कुछ लोगों को ठेस पहुंचती है, तो वह आपको रुककर सोचने और सुनने के लिए मजबूर करती है। एक अभिनेता के तौर पर मैं किसी फिल्म या सीरीज से अपने किरदार और कहानी के माध्यम से जुड़ता हूं। मेरे लिए यह एक कमियों से भरे व्यक्ति और उसकी आत्मबोध की यात्रा को दर्शाने का प्रयास था। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय के बारे में कोई बयान देना नहीं था।'

मनोज बाजपेयी ने अपने पोस्ट में निर्देशक नीरज पांडे के साथ अपने लंबे अनुभव का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा, 'नीरज पांडे के साथ काम करते हुए मैंने हमेशा यह देखा है कि वे अपनी फिल्मों को लेकर गंभीरता और सावधानी बरतते हैं। जनभावनाओं को देखते हुए फिल्म के मेकर्स ने सभी प्रमोशनल मटेरियल को हटाने का फैसला लिया है।'' विवाद तब शुरू हुआ जब नेटफ्लिक्स के 'नेक्स्ट ऑन नेटफ्लिक्स' इवेंट में 'घूसखोर पंडत' का फर्स्ट लुक और टीजर सामने आया। इसके तुरंत बाद फिल्म के टाइटल को लेकर आपत्तियां उठने लगीं। आलोचकों का कहना था कि 'घूसखोर' जैसे नकारात्मक शब्द के साथ 'पंडत' शब्द का इस्तेमाल ब्राह्मण समुदाय की छवि को ठेस पहुंचाता है। इसके बाद मुंबई के एक वकील ने लीगल नोटिस भेजा, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एफआईआर भी दर्ज की गई। भोपाल समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और फिल्म पर बैन की मांग की गई। विवाद बढ़ने के बाद निर्देशक नीरज पांडे ने भी आधिकारिक बयान जारी कर साफ किया कि यह एक पूरी तरह काल्पनिक पुलिस ड्रामा है और 'पंडत' शब्द सिर्फ एक फिक्शनल किरदार का बोलचाल का नाम है।

कॉकटेल 2 के बाद एक और फिल्म करेंगे शाहिद-रश्मिका

शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना आगामी फिल्म 'कॉकटेल 2' से चर्चा में है, जिसकी शूटिंग हाल ही में पूरी हुई। कृति सेनन भी फिल्म का हिस्सा हैं। इस बीच हालिया जानकारी में बताया गया है कि शाहिद और रश्मिका एक अन्य फिल्म के लिए साथ आ रहे हैं। दोनों से जब बिना टाइटल वाली आगामी फिल्म के लिए बातचीत की गई तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक...'शाहिद और रश्मिका 'बधाई हो' और 'मैदान' के निर्देशक अमित रविंद्रनाथ शर्मा की अगली फिल्म में साथ नजर आएंगे। यह अनाम फिल्म रोमांस और कॉमेडी का एक नया मिश्रण पेश करने का वादा करती है, जिसका निर्माण सुनीर खेत्रपाल, वर्मिलियन वर्ल्ड वैनर के तहत जियो स्टूडियोज के सहयोग से किया जाएगा। सुनीर इससे पहले जॉन अब्राहम स्टारर 'रॉकी हैंडसम', वरुण धवन की 'बदला' और 'फरें' जैसी फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं। इस रोमांटिक फिल्म की शूटिंग इसी साल अगस्त या सितंबर महीने से शुरू कर देंगे। फिलहाल अभिनेता अपनी आगामी फिल्म 'ओ रोमियो' के प्रचार में व्यस्त हैं जो 13 फरवरी को रिलीज हो रही है। इसके अलावा एक्टर ने अपनी वेब सीरीज 'फर्जी' के दूसरे सीजन को लेकर भी संकेत दे दिया है। राज और डीके द्वारा निर्मित इस सीरीज में उन्हें दोबारा सनी के किरदार में देखा जाएगा।

चिरंजीवी की अगली फिल्म में हुई अनुराग कश्यप की एंट्री

साउथ के मेगास्टार चिरंजीवी इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'मन शंकर वर प्रसाद गारु' की सफलता का जश्न मना रहे हैं। इस फिल्म को न सिर्फ दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों ने भी इसकी जमकर तारीफ की है। इसी बीच चिरंजीवी की अगली फिल्म को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक...' चिरंजीवी ने अपनी अगली फिल्म फाइनल कर ली है, जिसका ऐलान जल्द किया जाएगा। खास बात यह है कि इस फिल्म में बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक और अभिनेता अनुराग कश्यप भी नजर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि अनुराग फिल्म में एक अहम किरदार निभाएंगे। चिरंजीवी इस प्रोजेक्ट के लिए निर्देशक बॉबी के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। फिल्म का शुभारंभ फरवरी में किया जाएगा, जिसके तुरंत बाद शूटिंग शुरू होने की संभावना है।

क्या जल्द शादी रचाने वाले हैं कृतिका कामरा और गौरव कपूर?

अभिनेत्री कृतिका कामरा और क्रिकेट होस्ट गौरव कपूर इन दिनों अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में हैं। दोनों ने जब से अपने रिश्ते का आधिकारिक रूप से एलान किया है, तब से फैंस इनसे जुड़ी हर अपडेट पर नजर रखते हैं। अब ऐसी अफवाहें हैं कि कपल इस साल शादी रचा सकता है।

क्या 2026 में रचाने वाले हैं शादी?

कृतिका कामरा और गौरव कपूर को हाल के दिनों में कई इवेंट में साथ देखा गया है। दोनों के बीच आपसी समझ और केमिस्ट्री की फैंस काफी तारीफ करते हैं। इनके बीच शानदार दोस्ती और प्यार साफ नजर आता है। पिछले कुछ वीक में ऐसी अफवाहों ने जोर पकड़ा है कि कपल सात 2026 में शादी रचा सकता है। हालांकि, कृतिका और गौरव दोनों में से किसी ने भी इन रिपोर्ट्स पर सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, कपल के करीबी सूत्रों का कहना है कि दोनों की शादी की तैयारियां पहले से ही चल रही हो सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कपल मार्च के आखिर या अप्रैल 2026 की शुरुआत में अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर सकता है। खबरों के मुताबिक वेन्यू और गेस्ट लिस्ट को लेकर तैयारी चल रही है। दोनों से जुड़े करीबी लोगों का कहना है कि दोनों इस टाइमफ्रेम में शादी की संभावना को देखते हुए अपने प्रोफेशनल शेड्यूल को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, इस बारे में कपल के दोस्तों और जान-पहचान वालों ने कोई बयान जारी नहीं किया है। कृतिका या गौरव की तरफ से भी कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है।

आधिकारिक एलान का इंतजार

फिलहाल, दोनों की शादी को लेकर चल रही अफवाहों को लेकर फैंस उत्साहित हैं। इस कपल ने शुरू में अपने रिलेशनशिप को तब कन्फर्म किया था, जब कृतिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गौरव के साथ ब्रेकफास्ट डेट की कैंडिड तस्वीरें पोस्ट कीं। कैप्शन में उन्होंने बस इतना लिखा, 'ब्रेकफास्ट विद'। यह कैप्शन गौरव के पॉपुलर शो ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस की तरफ हिंट था। फिलहाल दोनों ने अपने रिलेशनशिप की डिटेल्स को प्राइवेट रखा है। फैंस को इंतजार है कि कब दोनों शादी से जुड़ी अपडेट साझा करते हैं!

चाहत पांडे ने ओटीटी की दुनिया में रखा कदम

टीवी और रियलिटी शो की दुनिया में अपनी पहचान बना रही एक्ट्रेस चाहत पांडे ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी डेब्यू किया है। हंगामा ओटीटी पर रिलीज हुई नई वेब सीरीज 'हसरतें सीजन 3' में उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण किरदार निभाया है। उनका किरदार कई मायनों में महिलाओं की जटिल भावनाओं, उनकी इच्छाओं और उनके संघर्ष को बयां करता है। सीरीज के नए एपिसोड 'नया किराएदार' में चाहत पांडे ने स्मिता नाम की गृहिणी की भूमिका निभाई है। स्मिता एक ऐसी महिला है, जो अपने पति के अचानक गायब होने के बाद अकेली और भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस करती है। उसे अपनी दबंग सास के साथ रहना पड़ता है, जिससे उसके जीवन में दबाव और भी बढ़ जाता है। समाज की निगाहें, ऑफिस में हो रहे उत्पीड़न और अपनी अधूरी इच्छाओं को दबाने की मजबूरी ने उसकी जिंदगी को थमा दिया है। लेकिन कहानी में बदलाव तब आता है, जब उसके घर में समर्थ नाम का एक युवा म्यूजिशियन किरायेदार बनकर आता है। उनकी बढ़ती दोस्ती स्मिता के भीतर छिपी हुई भावनाओं को फिर से जागृत करती है। जैसे-जैसे स्मिता समर्थ के करीब जाने लगती है, अचानक उसके पति की वापसी हो जाती है। स्मिता को अब यह तय करना होता है कि वह समाज की बनाई गई मर्यादाओं और पारिवारिक जिम्मेदारियों में बंधी रहे या अपनी खुशी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को चुने। यह कहानी दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करेगी कि कभी-कभी जीवन में अपनी खुशी चुनना गुनाह नहीं, बल्कि जीवित रहने का तरीका है। चाहत पांडे ने अपने किरदार को लेकर कहा, ''स्मिता मेरे करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण किरदार है। स्मिता ऐसी महिला है, जिसे बचपन से सिखाया गया कि उसे अपने दर्द और अधूरी इच्छाओं को कभी व्यक्त नहीं करना है। पति के गायब होने के बाद समाज उसे और भी सख्ती से नियंत्रित करने लगता है। इस किरदार के जरिए मैंने यह दिखाने की कोशिश की कि जब एक महिला अपनी आवाज सुनती है, तो उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है।'' चाहत ने आगे कहा, ''स्मिता की कहानी उसके अधिकारों को वापस पाने और यह स्वीकार करने की कहानी है कि अपनी खुशी चुनना कोई अपराध नहीं है। यह किरदार महिलाओं की भावनाओं, उनके संघर्ष और उनकी स्वतंत्रता की कहानी को बड़े ही संवेदनशील तरीके से पेश करता है।'' 'हसरतें सीजन 3' में चाहत पांडे का यह कदम ओटीटी की दुनिया में उनकी नई पहचान बनाने का भी अवसर है। दर्शक न केवल उनकी भावनाओं से जुड़ेंगे, बल्कि उनकी कहानी के माध्यम से समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों के महत्व को भी महसूस करेंगे।

सिद्धांत चतुर्वेदी ने यूपी की जड़ों और भोजपुरी के साथ भाषा से जुड़ी चुनौतियों पर की खुलकर बात

अनगिनत युवाओं की कहानी है, जो सपनों के साथ एक शहर से दूसरे शहर आते हैं। दिलचस्प बात ये है कि भाषा, पहचान और आत्मविश्वास पर बिना किसी चमक-दमक के बात करते हुए सिद्धांत चतुर्वेदी एक बार फिर साबित करते हैं कि दर्शक उनसे इसलिए जुड़ाव महसूस करते हैं क्योंकि वे खुद एक ऐसे कलाकार के रूप में उनसे जुड़ते हैं, जिनकी यात्रा बनावटी नहीं, बल्कि सच्ची, मेहनत से अर्जित की गई और गहराई से भारतीय है।

अपनी आगामी तथा चर्चित फिल्म 'दो दीवाने सहर में' के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर सिद्धांत चतुर्वेदी ने एक बेहद निजी और भावनात्मक पहलू साझा किया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में पले-बढ़े सिद्धांत ने अपनी जड़ों, भोजपुरी भाषा और मुंबई आने के बाद भाषा व आत्मविश्वास से जुड़ी उन खामोश चुनौतियों पर खासखबर के साथ खुलकर बात की, जिनका सामना अक्सर बाहर से आने वाले युवाओं को करना पड़ता है। अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए सिद्धांत ने बताया कि बलिया में बिताया गया बचपन न सिर्फ उनके उच्चारण बल्कि उनकी सोच का भी अहम हिस्सा रहा है। श को स कहने के बारे में वे कहते हैं, 'घर में बातचीत की भाषा भोजपुरी थी और आज भी मेरी मां भगवान शिव को प्यार से 'संकर भगवान' कहती हैं।' हालांकि सिद्धांत के लिए ये सिर्फ यादें नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव हैं, जो 'दो दीवाने सहर में' की स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त और गहरे हो गए थे। खासखबर से बातचीत में सिद्धांत आगे कहते हैं, 'मेरे लिए यह हमेशा से काफी पर्सनल रहा है। जब मैं मुंबई आया, तो पहले पांच-छह साल मेरी हिंदी भी टूटी-फूटी थी। मैं भोजपुरी में ही बात करता था।' उन्होंने यह भी बताया कि भाषा किस तरह धीरे-धीरे आत्मविश्वास को प्रभावित करती है, खासकर तब, जब आप अपनी क्षेत्रीय पहचान के साथ किसी बड़े शहर में कदम रखते हैं। हालांकि टूटी हिंदी में बात करना, धीरे-धीरे अंग्रेजी सीखना और 'स' व 'श' जैसे उच्चारणों को लेकर सजग होना, ये सब ऐसी बातें हैं, जिनसे कई लोग गुजरते हैं, लेकिन कम ही खुलकर बोलते हैं।

'बात यह नहीं है कि आप यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, नॉर्थ-ईस्ट या नेपाल से आते हैं, बात ये है कि भाषा की दीवार होती ही है। और जब आप किसी चीज को लेकर कॉन्शस हो जाते हैं, तो वह आपके आत्मविश्वास को प्रभावित करती है।' सिद्धांत ने कहा। गौरतलब है कि बेहद भावुकता के साथ कहे अपने दिल की बात को और भी मानवीय बना देती है सिद्धांत की ईमानदारी, जिसमें उन्होंने सीखने और खुद को ढालने की प्रक्रिया को बिना किसी दिखावे के स्वीकार किया।

उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने बिना किसी औपचारिक ट्रेनिंग के, जीवन के अनुभवों से बोलचाल सुधारी। यहां तक कि फर्राटेदार अंग्रेजी बोलनेवाली चेन्नई की लड़की के साथ पहली बार प्यार में पड़ना भी उनके लिए भावनात्मक ही नहीं, भाषाई सीख का भी हिस्सा था। हालांकि उनकी सच्ची और बिना बनावट की बातों ने 'दो दीवाने शहर में' में उनके किरदार को और गहराई दी है, जहां भावनात्मक संवेदनशीलता और सच्चाई कहानी का केंद्र है।

घर की भोजपुरी बातचीत से लेकर हिंदी सिनेमा में अपनी आवाज खोजने तक का सिद्धांत का सफर उन

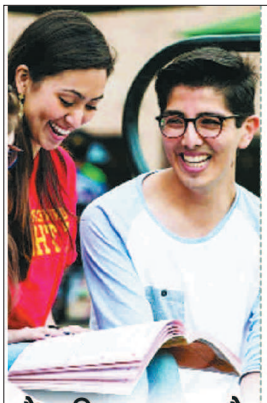

रैंक डिसाइड करता है निबंध, इन टिप्स की मदद से करें तैयारी

निबंध लेखन यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा का अनिवार्य और एक महत्वपूर्ण भाग है। निबंध का पेपर सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के नौ पेपरों में से एक है। इस पेपर में आपको दो निबंध लिखने होंगे, जिनमें से प्रत्येक की शब्द सीमा 1000 - 1200 होगी। उम्मीदवारों को चार विषयों में से एक विषय का चयन करने के लिए दिया जाएगा।

निबंध का पेपर कुल 250 अंकों का होता है, जिसमें एक निबंध 125 अंकों का होता है। इस पेपर के लिए एक बेहतर स्ट्रेटेजी बनाकर तैयार करना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं टॉपर की तरफ से तैयारी के कौन-से टिप्स दिए गए हैं।

इंट्रोडक्शन में पाठक को लुभाने की हो ताकत

निबंध की शुरुआत इंट्रोडक्शन से होती है यही कारण है कि इसका सबसे अधिक आकर्षक होना आवश्यक है। टॉपर्स का कहना है कि इंट्रोडक्शन एक बेहतर निबंध का मूल मंत्र है।

डाटा और फैक्ट्स से निबंध होगा मजबूत

टॉपर्स का कहना है कि निबंध में ज्यादा से ज्यादा डाटा और फैक्ट्स शामिल करने का प्रयास करें। ऐसा करने से न सिर्फ आपका निबंध विश्वसनीय बनेगा साथ ही आपको बेहतर अंक भी मिल सकते हैं।

रोज योजना मैगजीन पढ़ें

निबंध लिखने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रोज योजना मैगजीन पढ़ें। योजना मैगजीन पढ़ने से आपको यह आइडिया हो जाएगा कि सरकारी निबंध कैसे लिखे जाते हैं। उम्मीदवार इस स्ट्रेटेजी को जरूर अपनाएं।

असल जिंदगी के उदाहरण करें शामिल

एक बेहतर निबंध लिखने के लिए आवश्यक है कि सभी पाठकों को उससे जुड़ जाए। ऐसा करने के लिए उम्मीदवार लिखते समय असल जिंदगी से जुड़े हुए उदाहरण या किस्से कहानियां लिख सकते हैं। यह निबंध को अधिक सरल और रोचक बना देती है।

नौकरीपेशा लोगों के लिए बेहतर विकल्प है डिस्टेंस एजुकेशन

अगर आप किसी कारणों से नियमित कॉलेज नहीं जा सकें हो तो डिस्टेंस एजुकेशन एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। डिस्टेंस एजुकेशन से मिलने वाली डिग्री भी रेगुलर की तरह ही होती है जिसका इस्तेमाल आप अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं।

भारत जैसे देश में जहां आज भी बहुत सारे जिलों में कॉलेज या यनिवर्सिटीज नहीं हैं, वहां डिस्टेंस एजुकेशन का माध्यम खासा लोकप्रिय है। यह एक लचीला माध्यम है, जो छात्रों को पढ़ाई के दौरान दूसरे शौक को भी पूरा करने की छूट देता है। सबसे बड़ी बात यह कि यह कामकाजी और नौकरीपेशा वाले लोगों को भी उच्च शिक्षा की राह दिखा रहा है। इन डिस्टेंस लर्निंग सेंटर में डिप्लोमा, बैचलर डिग्री और पीजी व मैनेजमेंट कोर्स चलाए जाते हैं। कई डिस्टेंस लर्निंग सेंटर प्रोफेशनल कोर्स भी संचालित करते हैं जो रोजगारोन्मुख होते हैं। इनमें जर्नलिज्म एंड मास निकेशन, लाइब्रेरी साइंस, कम्प्यूटर कोर्सेस आदि शामिल है।

ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना मुश्किल नहीं हैं। ये यूनिवर्सिटीज अपने नियमों के मामले में काफी लचीली होती हैं। यहां कोर्स की फीस भी अमूमन सामान्य संस्थानों के मुकाबले कम होती है। अकादमिक जानकारियों के लिए इन यूनिवर्सिटीज के कोर्स बेस्ट माने जाते हैं। कई यूनिवर्सिटीज में वीकएंड क्लासेज होती हैं, जिससे कामकाजी लोगों को सहूलियत होती है। पढ़ाई और नौकरी के बीच के समय का इस्तेमाल करने वालों के लिए ये यूनिवर्सिटीज ई-क्लास से लेकर छोटी अवधि वाली रेगुलर क्लासेज तक चला रही हैं।

इग्नू और डिस्टेंस एजुकेशन

जो युवा नियमित कॉलेज नहीं जा सकते हैं, उनके लिए पढ़ाई करने और करियर बनाने के लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इग्नू की पढ़ाई का तरीका अन्य पारंपरिक यूनिवर्सिटीज से अलग है। इग्नू ने पढ़ाई का एक मल्टीमीडिया नजरिया अपनाया है। विज्ञान, कम्प्यूटर, नर्सिंग, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में पाठ्यक्रम भी शामिल है। यहां बीए जनरल कोर्स के साथ ही बीएससी जनरल की पढ़ाई भी होती है, जिसमें गणित, भौतिकी, रसायन, बॉटनी और जूलॉजी जैसे विषय भी पढ़ाए जाते हैं। यहां बीकॉम भी है। इसके अलावा बीबीए इन रिटेलिंग, बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज, बैचलर ऑफ सोशल वर्क और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लिकेशन जैसे कोर्स हैं। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग के रूप में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स भी है। यहां बीएड और डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी डीएड कोर्स भी अब डिस्टेंस एजुकेशन में शामिल हो गया है।

डिस्टेंस एजुकेशन की ये हैं विशेषताएं

- डिस्टेंस एजुकेशन में स्टूडेंट को नियमित तौर पर किसी संस्थान में जाकर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती।
- सूचना क्रांति और इन्टरनेट के कारण डिस्टेंस एजुकेशन और आसान एवं प्रासंगिक हो गयी है।
- विजुअल क्लासरूम लर्निंग, इंटरैक्टिव ऑनसाइट लर्निंग और वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए स्टूडेंट्स देश के किसी भी राज्य में रहकर घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं।
- डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई करने की फीस काफी कम है।
- जॉब करने के साथ-साथ पढ़ाई की जा सकती है।
- कम अंक आने पर भी मनपसंद कोर्स में दाखिला मिल जाता है।
- किसी भी कोर्स के लिए उम्र बाधा नहीं होती है।
- साधारण कोर्स के साथ ही वोकेशनल कोर्स तथा प्रोफेशनल कोर्स भी किये जा सकते हैं।

ये हैं प्रमुख डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर्स:

इग्नू, दिल्ली
सिम्बायोसिस सेंटर फॉर डिस्टेंट लर्निंग, पुणे
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली
अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु
पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, पुडुडुचेरी
हिमाचल यूनिवर्सिटी, शिमला
गुरु जंभेश्वर, हिसार
एमडीयू, रोहतक
पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी
सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी

नए ऑफिस में बनाना है इम्प्रेशन तो ये ट्राय करके देखिए

जानते हैं कुछ टिप्स जिनसे आप नई वर्कप्लेस में खुद की क्षमताओं को साबित कर सकेंगे। करियर ग्रोथ के लिए लोग कई बार जॉब बदलकर नई कंपनी जॉइन करते हैं। जाहिर है, नई जगह एडजस्टमेंट में थोड़ी दिक्कत तो होती ही है। जानते हैं कुछ टिप्स जिनसे आप नई वर्कप्लेस में खुद की क्षमताओं को साबित कर सकेंगे।

अहम हैं पहले दो सप्ताह

हर कंपनी अपने नए एंप्लॉइज को कुछ दिन बिना किसी खास असाइनमेंट के ऑफिस में एडजस्ट करने का समय देती है। इस समय का फायदा उठाएं। छोटी-से-छोटी बातों को नोट करें। कंफ्यूज हो, तो सवाल पूछें, लेकिन एक ही सवाल बार-बार पूछने से लोग खीज जाते हैं। विनम्र रहें और हर बात पर अपना नजरिया रखने से बचें।

दोस्ती की जल्दी न करें

लोगों को जज करने में जल्दबाजी न करें। लोगों के बारे में बिना सोचे-समझे अपनी धारणा न बनाएं। साथ ही, ऑफिस गॉसिप से भी दूर रहें। लोगों को जानने के लिए अपना समय लें। सबसे एक जैसा व्यवहार करें। दोस्ती करने के लिए जबर्दस्ती किसी ग्रुप में शामिल होने की कोशिश न करें।

बनाएं सही संतुलन

नई जॉब में दूसरों पर निर्भरता ज्यादा होती है, इसीलिए अक्सर लोग फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। ऐसे में अपना धैर्य बनाए रखें। हो सकता है कि कंपनी आपसे जॉइनिंग के कुछ ही दिन में परफॉर्मेंस की उम्मीद करे। ऐसे में सीनियर्स की मदद और खुद की परफॉर्मेंस में बैलेंस बनाने पर ध्यान दें।

चमचागिरी नहीं

जब आपका बॉस आपसे खुश होता है, तो आपकी वर्क-लाइफ भी काफी अच्छी रहती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपना काम छोड़कर सिर्फ बॉस को खुश करने पर ही ध्यान दें। याद रखिए, आपकी परफॉर्मेंस आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से बोलती है। इसलिए काम में लापरवाही न करें।

रिकॉर्ड हों व्यवस्थित

रिकॉर्ड्स मेंटेन रखना एक अच्छे एंप्लॉयी की निशानी है, इसलिए अपनी वर्क-प्रोफाइल से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स और मेल्स को मेंटेन रखें। इससे एक बैकअप हमेशा आपके पास रहेगा और कोई आप पर बेवजह दबाव नहीं बना पाएगा।

बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय

आज जब एक ओर पशुओं के चारे दाने एवं दवाएं महँगी होने से पशुपालन आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो गया हैं । ऐसे में बकरी पालन कम लागत एवं सामान्य देखरेख में गरीब किसानों एवं खेतिहर मजदूरों के जीविकोपार्जन का एक मजबूत साधन बन रहा हैं । इतना ही नहीं इससे होने वाली आय समाज के आर्थिक रूप से सम्पन्न लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं । बकरी पालन स्वरोजगार का एक प्रबल साधन बन रहा है। बकरी एक पालतु पशु है जिसे दूध तथा मांस के लिये पाला जाता है । इसके अतिरिक्त इससे चमड़ा, बाल, रेशा तथा खाद प्राप्त होता है । वातावरण एवं वरणात्मक प्रजनन ने बकरी की कई नस्लों को तैयार किया, जो विभिन्न स्थानों पर उपयोग के अनुसार पाई जाती हैं । आज भारत में लगभग 20 उन्नत नस्लें पाई जाती हैं । बकरी पालन का एक लाभकारी पहलू यह है कि इसे महिलाएं भी आसानी से पाल सकती हैं । वर्तमान में बकरी व्यवसाय की लोकप्रियता तथा सफलता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसका व्यवसायीकरण हो रहा हैं । औद्योगिक घराने तथा व्यवसायी बकरी पालन पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है और बड़े बड़े बकरी फार्म सफलतापूर्वक चल रहे हैं । भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में बकरी जैसा छोटे आकार का पशु भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा हैं । विगत 2-3 दशकों में बढ़ी हुई वध दर के बावजूद विकासशील देशों में बकरियों की संख्या में निरंतर वृद्धि, इनके सामाजिक एवं आर्थिक महत्व को दर्शाती हैं । प्राकृतिक रूप से निम्न कारक बकरी विकास दर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं और इन्हीं कारणों से बकरी का एक विशेष स्थान है - बकरी का विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में ढालने की क्षमता रखना । इसी गुण के कारण बकरियां देश के विभिन्न भौगोलिक भूभागों में पाई जाती हैं। बकरी की अनेक नस्लों का एक से अधिक बच्चा देने की क्षमता रखना । बकरी की ब्याने के उपरांत अन्य पशु प्रजातियों की तुलना में पुन- जनने के लिये जल्दी तैयार हो जाना ।

बकरी पालन प्राय- सभी जलवायु में कम लागत, साधारण आवास, सामान्य रख-रखाव तथा पालन पोषण के साथ संभव है । इसके उत्पाद की बिक्री हेतु बाजार सर्वत्र उपलब्ध है।

बकरी पालन की उपयोगिता

आज जब एक ओर पशुओं के चारे दाने एवं दवाएं महँगी होने से पशुपालन आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो गया हैं । ऐसे में बकरी पालन कम लागत एवं सामान्य देखरेख में गरीब किसानों एवं खेतिहर मजदूरों के जीविकोपार्जन का एक मजबूत साधन बन रहा हैं । इतना ही नहीं इससे होने वाली आय समाज के आर्थिक रूप से सम्पन्न लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं । बकरी पालन स्वरोजगार का एक प्रबल साधन बन रहा है। बकरी पालन मुख्य रूप से मांस, दूध तथा रोआ (पसमिना एवं मोहेर) के लिये किया जा सकता हैं । हमारे क्षेत्र में पाई जाने वाली बकरियां वयस्क होकर दो वर्ष में कम से कम 3 बार बच्चों को जन्म देती हैं और एक वियान में 1 से 2 बच्चों को जन्म देती हैं ।

बकरियों से मांस, दूध, खाल एवं रोआ के अतिरिक्त इसके मल-मूत्र से जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती हैं । बकरियां प्राय- चारागाह पर निर्भर रहती हैं । यह झाड़ियाँ, जंगली घास तथा पेड़ के पत्तों को खाकर हम लोगो के लिये पौष्टिक पदार्थ जैसे मांस एवं दूध उत्पादित करती हैं।

बकरी पालन हेतु कुछ सावधानियां

- बकरा बकरी को अलग अलग रखना चाहिये।
- प्रथम प्रजनन 8 से 10 माह के बाद ही कराना चाहिये।
- बच्चा देने के बाद कम से कम 30 बाद ही पुन- प्रजनन करायें ।
- बकरी के बच्चों को ठंड से बचाना चाहिये।
- नर बच्चों का बधियाकरण 2 माह की उम्र में कराएं ।
- बकरियों का नियमित टीकाकरण कराएं तथा कृमिनाशक दवा दें ।
- आवास हमेशा साफ सुथरा रखें।

शहर में सामाजिक सक्रियता की मिसाल बने इंद्रजीत, वर-वधु को सुखमय दांपत्य जीवन की दी बधाई

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर एवं सर्व समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह (छोटू) शहर में लगातार सामाजिक, धार्मिक एवं पारिवारिक आयोजनों में सक्रिय सहभागिता निभा रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में उपस्थित होकर उन्होंने समाज के सभी वर्गों से जुड़ाव मजबूत किया और सहयोग का संदेश दिया।

सेक्टर-6 स्थित सतनाम भवन में सुरेंद्र कुमार गजभिये के सुपुत्र राहुल के वैवाहिक कार्यक्रम में इंद्रजीत सिंह सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने वर-वधु को सुखमय दांपत्य जीवन की

शुभकामनाएं देते हुए परिवारजनों को हार्दिक बधाई दी।

इसी क्रम में नेहरू नगर, भिलाई में डॉ. अनिल शुक्ला जी के नव-निर्मित मकान के गृहप्रवेश कार्यक्रम में भी उन्होंने सहभागिता की। उन्होंने परिवार को नए गृह के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य एवं खुशहाली की कामना की।

सुपेला स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी में साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी के जन्म दिहाड़ा के अवसर पर आयोजित 16वें विशेष गुरमत समागम में भी वे उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उन्होंने संगत को बधाई देते हुए सामाजिक एकता एवं सद्भाव का संदेश दिया।

न्यू दीनदयाल आवासीय परिसर, खम्हरिया (वार्ड क्रमांक 01) में श्री शिव मंदिर समिति द्वारा आयोजित प्राण प्रतिष्ठा एवं विशेष पूजन कार्यक्रम में भी उन्होंने सहभागिता की और आयोजन की सराहना की। कर्मा भवन, सुपेला भिलाई में आयोजित रेड ड्रॉप संस्था के 13वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश स्तरीय सामाजिक संस्थाओं के सम्मान समारोह एवं चिकित्सा व रक्तदान शिविर में भी इंद्रजीत सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने रक्तदाताओं को हेलमेट भेंट कर सम्मानित किया तथा रक्तदान जैसे पुनीत कार्य के लिए सभी की सराहना की। युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रक्तदान जीवनदान है और समाजहित में ऐसे कार्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने रेड ड्रॉप संस्था के सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी प्रेषित कीं।

उल्लेखनीय है कि इंद्रजीत सिंह छोटू शहर में निरंतर सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। वे ब्लड डोनेशन कार्यक्रमों, अस्पतालों में मरीजों से मुलाकात, जरूरतमंदों को राशन वितरण, शिक्षा एवं खेल गतिविधियों के प्रोत्साहन तथा विभिन्न सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में बढ़-चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। समाज के सभी वर्गों से उनका सतत संपर्क बना हुआ है और वे समान रूप से सहयोग प्रदान कर सामाजिक समरसता को मजबूत करने में योगदान दे रहे हैं।

खास खबर

चांदमारी रोड पर फिल्मी स्टाइल में छेड़खानी, एक आरोपी गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / रायगढ़

चांदमारी रोड पर कार सवार दो युवतियों से छेड़खानी की गंभीर घटना पर रायगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना में प्रयुक्त ग्रैंड विटारा कार क्रमांक CG13 AW 2410 भी जप्त कर ली गई है। मामले में शामिल अन्य चार आरोपी फरार हैं, जिनकी सघन तलाश जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में महिला थाना पुलिस ने तत्काल छापेमारी की कार्रवाई की।

क्या है पूरा मामला : पीड़िता ने 10 फरवरी को महिला थाना में आवेदन देकर बताया कि 9 फरवरी की रात करीब 11 बजे वह अपनी ममेरी बहन के साथ कार से रायगढ़ दवाई लेने जा रही थीं। चांदमारी रोड पर कार रोककर वे आवारा कुत्तों को बिस्किट खिला रही थीं, तभी पीछे से नीले रंग की ग्रैंड विटारा कार में सवार पांच युवक पहुंचे और अशोभनीय टिप्पणियां व गंदे इशारे करने लगे। दोनों युवतियां वहां से निकल गईं, लेकिन आरोपियों ने उनका पीछा किया। रियाणा तिराहा चौक के पास आरोपियों ने ओवरटेक कर उनकी कार के सामने अपनी गाड़ी अड़ा दी। एक युवक कार से उतरकर अभद्र हरकतें करते हुए अपना नाम प्रदीप पटेल बताया, जबकि अन्य साथी भी अश्लील टिप्पणियां करते रहे। महिला थाना में अपराध क्रमांक 09/2026 के तहत धारा 78(2), 126(2), 79, 75(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस लाइन और कोतवाली थाना स्टाफ के साथ आरोपियों की तलाश में दबिश दी गई।

जांच के दौरान ग्रैंड विटारा कार डिमरापुर स्थित प्रदीप पटेल के घर के सामने मिली, लेकिन वह फरार था। आगे की जांच में सामने आया कि घटना के दिन वाहन नरेन्द्र महावर चला रहा था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी नरेन्द्र महावर (21 वर्ष), निवासी वार्ड नं. 1 चांवसारी भवानी स्कूल के पास, थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पूछताछ में उसने प्रदीप पटेल, कमलेश यादव, राहुल गुप्ता और संगम त्रिपाठी निवासी सतीगुड़ी चौक रायगढ़ के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। अन्य चार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है।

संतोष अग्रवाल बने डॉक्टर रमन के विधायक प्रतिनिधि

राजनांदगांव। पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष अग्रवाल को राजनांदगांव विधायक का विधायक प्रतिनिधि मनोनीत किया है। संतोष अग्रवाल के मनोनयन से कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। पूर्व मंडल महामंत्री कृष्णा तिवारी ने संतोष अग्रवाल के मनोनीत होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी। आपके नेतृत्व में जनहित के कार्य और अधिक प्रभावी रूप से आगे बढ़ें, यही शुभेच्छा है। सफल एवं उज्ज्वल कार्यकाल की मंगलकामनाएँ।

ठाकुर टोला टोल प्लाजा पर शुल्क वसूली को लेकर सवाल, उच्च स्तरीय जांच की मांग

24 घंटे के भीतर वापसी पर भी लगता है टैक्स, फास्टटेग खाते से भी राशि काटने के बाद देर से मिलती है जानकारी

नरेन्द्र डाकलिया / राजनांदगांव

राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ठाकुर टोला टोल प्लाजा एक बार फिर शुल्क आरसी वसूली और फास्टैग कटौती प्रणाली को लेकर विवादों में है। स्थानीय नागरिक वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र कुमार जैन ने नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को औपचारिक शिकायत/विधिक नोटिस प्रेषित कर गंभीर अनियमितताओं की आशंका जताई है।

प्रेषित शिकायत में कहा गया है कि टोल प्लाजा पर Return Journey (24 घंटे के भीतर वापसी) से संबंधित रियायत का व्यवहारिक अनुपालन नहीं हो रहा। नियमों के अनुसार 24 घंटे के भीतर उसी टोल से वापसी करने वाले वाहनों को रियायती शुल्क मिलना चाहिए, किंतु कई मामलों में पूर्ण टोल शुल्क कटने की बात सामने आई है। शिकायत में फास्टटैग प्रणाली की पारदर्शिता पर भी प्रश्न उठाए गए हैं। आवेदनकर्ता का आरोप है कि कई अवसरों पर FASTag खाते से राशि कटने के बावजूद SMS/Notification प्राप्त नहीं होता, जिससे वाहन चालकों को तत्काल जानकारी नहीं मिलती।

यह मार्ग राजनांदगांव–दुर्ग–रायपुर कॉरिडोर का अत्यंत व्यस्त खंड माना जाता है, जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों–हजारों वाहनों का आवागमन होता है। ऐसे में शुल्क प्रणाली में किसी भी प्रकार की त्रुटि या विसंगति से राजस्व पर व्यापक प्रभाव की संभावना व्यक्त की गई है। आवेदनकर्ता ने पत्र में उल्लेख किया है कि परिस्थितियाँ करोड़ों रुपये के संभावित राजस्व अंतर की आशंका उत्पन्न करती हैं, जिसके लिए उच्च स्तरीय तकनीकी एवं वित्तीय जांच (System / Transaction Audit) आवश्यक है।

शिकायत में NHAI से मांग की गई है कि —Return Journey (24 घंटे) रियायत के वास्तविक अनुपालन का सत्यापन किया जाए, FASTag ट्रांजैक्शन लॉग एवं सूचना प्रणाली का परीक्षण किया जाए, तथा यदि अनियमितता पाई जाए तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। प्रकरण को लेकर अब स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। नागरिकों का कहना है कि टोल एवं FASTag प्रणाली में पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा सवीपरि होनी चाहिए।

तैंतीस हितग्राहियों के अपने घर का सपना हुआ साकार, लगी लाटरी

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भिलाई शहर में निवास कर रहे नागरिक जिनके पास स्वयं का पक्का मकान नहीं है, उन्हे सरकार द्वारा पक्का मकान उपलब्ध कराने की योजना चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत नागरिकों को न्यूनतम दर पर पक्का मकान दिया जा रहा है।

नागरिक नियमानुसार नगर निगम भिलाई के आवास शाखा में आवेदन किये है। आवेदक द्वारा जमा किये गये आवेदनों का सक्षम स्वीकृति लेने पश्चात आवास आबंटन की लाटरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज निगम सभागार कक्ष में कुल 33 पात्र हितग्राहियों का लाटरी निकालकर आवास आबंटित किया गया है। लाटरी के दौरान आवास प्रभारी विदयाधर देवांगन, सीएलटीसी किरण चतुर्वेदी, नम्रता ठाकुर, जी मोहन राव, नूतन साहू सहित अन्य कमचारी उपस्थित रहें।

शासन के महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मकानहीन परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई सभागार कक्ष में प्रधानमंत्री आवास आबंटन की लाटरी का आयोजन किया गया।

लाटरी कार्यक्रम में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, सभापति गिरवर बंटी साहू, आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय, नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा, भाजपा जिला अध्यक्ष पुरूषोत्तम देवांगन, महापौर परिषद के सदस्य संदीप निरंकारी, पार्षद महेश वर्मा, सांसद प्रतिनिधि प्रमोद सिंह, पार्षद हरिओम तिवारी एवं अधीक्षण अभियंता सह आवास नोडल अधिकारी अजीत तिग्गा की उपस्थिति में 33 हितग्राहियों को आवास आबंटित किया गया है।

केवल्य धाम के पीछे महिला की सड़ी-गली लाश मिलने से मची खलबली

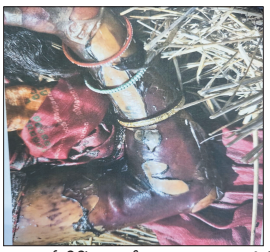

नई दृष्टिबिंदु / कुम्हारी

थाना कुम्हारी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परसादा खार में स्थित केवल्य धाम के पीछे एक अज्ञात महिला का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के अनुसार शव की स्थिति को देखते हुए अनुमान है कि महिला की मृत्यु लगभग 10 से 15 दिन पूर्व हुई होगी।

घटना की सूचना 17 जनवरी 2026 को मिलने पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्यवाही के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। थाना कुम्हारी में मर्ग कायम कर वैधानिक जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतका की उम्र लगभग 40–45 वर्ष के बीच है। महिला के हाथ पर विनोद शर्मा नाम का टैटू अंकित है, जो उसकी पहचान में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। अब तक महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है। शव की स्थिति अत्यंत खराब होने के कारण तत्काल पहचान संभव नहीं हो पाई। पुलिस ने घटनास्थल से महिला द्वारा पहने गए वस्त्र, चूड़ी, कंगन और चप्पल जब्त किए हैं। पहचान के लिए इनकी तस्वीरें भी साझा की जा रही हैं।

जनता से अपील

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि टैटू, हुलिया या बरामद वस्त्रों के आधार पर किसी को महिला के संबंध में कोई जानकारी हो तो तत्काल थाना कुम्हारी या निकटतम पुलिस थाना में संपर्क करें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और आसपास के क्षेत्र में गुमशुदगी की रिपोर्टों का भी मिलान किया जा रहा है।

ऑनलाइन ठगी का म्यूल अकाउंट बेनकाब! सुपेला पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

साइबर ठगी के खिलाफ दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना सुपेला पुलिस ने म्यूल अकाउंट के माध्यम से ऑनलाइन धोखाधड़ी की रकम ट्रांसफर करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई भारत सरकार के गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल से प्राप्त सूचना के आधार पर की गई।

जांच में खुलासा हुआ कि एचडीएफसी बैंक सुपेला शाखा में खोले गए एक खाते में 01 जून 2025 से 11 फरवरी 2026 के बीच कुल 3,05,273/- की संदिग्ध ऑनलाइन राशि जमा की गई थी।

पुलिस जांच में सामने आया कि उक्त बैंक खाता ऑनलाइन ठगी की रकम प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयोग किया जा रहा था। मामले में आरोपी रूपेश बोबड़े (32 वर्ष) निवासी अनंतपुरम, जुनवानी, स्मृति नगर, सुपेला को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 246/2026 के तहत धारा 317(2) एवं 318(4) भारतीय न्याय संहिता (डठर) में प्रकरण दर्ज कर विधिवत कार्रवाई की गई है। विवेचना जारी है।

जप्त सामग्री में बैंक खाते से संबंधित दस्तावेज, संदिग्ध लेनदेन का बैंक शामिल है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक विजय यादव, सहायक उप निरीक्षक पूरन लाल साहू एवं प्रधान आरक्षक सुबोध पाण्डेय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी ऑनलाइन लेनदेन में अपना बैंक खाता, ओटीपी या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें। किसी भी संदिग्ध साइबर गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दें।

अपराध | 26 प्रकरणों से जुड़े खातों का खुलासा

साइबर ठगी पर दुर्ग पुलिस का बड़ा एक्शन, 6 खाताधारकों पर कार्रवाई

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

जिले में बढ़ते साइबर अपराधों पर नकेल कसते हुए दुर्ग पुलिस की साइबर सेल ने विशेष अभियान चलाकर 06 खाताधारकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की है। जांच में सामने आया कि विभिन्न बैंकों के खातों में ठगी की रकम जमा कर चेक एवं अन्य माध्यमों से उसका लेन-देन और आहरण किया जा रहा था।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में साइबर धोखाधड़ी के दर्ज प्रकरणों की समीक्षा के दौरान संदिग्ध खातों की जानकारी मिली। 11 फरवरी 2026 को विशेष टीम गठित कर अभियान चलाया गया, जिसमें 06 खाताधारकों को चिन्हित कर पूछताछ की गई और विधिसम्मत कार्यवाही प्रारंभ की गई।

26 प्रकरणों से जुड़ा एक खाता, लाखों का लेन-देन

जांच में खुलासा हुआ कि एक बैंक खाता कुल 26 साइबर शिकायतों से जुड़ा हुआ है। एक अन्य खाते में 13 लाख रुपये की संदिग्ध राशि का लेन-देन पाया गया। इसके अलावा 15,000 रुपये, 38,800 रुपये और यहां तक कि 50 लाख रुपये तक की राशि विभिन्न खातों के माध्यम से ट्रांजेक्शन में शामिल पाई गई।

संबंधित प्रकरणों में पूर्व से अपराध पंजीबद्ध हैं, जबकि अन्य मामलों में नए अपराध क्रमांक दर्ज कर विवेचना जारी है। जिन खाताधारकों पर हुई कार्रवाई रूपेश बंजारे, निवासी दुर्ग, आजेंद्र साहू, निवासी दुर्ग, जावेद शेख, निवासी दुर्ग, सरस्वती निषाद, निवासी दुर्ग, हेमा बिनानी, निवासी दुर्ग और अभिषेक गुप्ता, निवासी दुर्ग शामिल हैं।

जप्त सामग्री में संबंधित बैंक खातों के दस्तावेज, लेन-देन संबंधी अभिलेख और चेक एवं अन्य बैंकिंग दस्तावेज शामिल हैं। इस कार्रवाई में साइबर सेल दुर्ग के प्रभारी अधिकारी, उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों एवं तकनीकी टीम की सक्रिय और समन्वित भूमिका रही। पुलिस की अपील- दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी से संबंधित कॉल, लिंक या बैंकिंग जानकारी साझा न करें। किसी भी संदिग्ध लेन-देन की सूचना तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 या निकटतम थाना में दें। साइबर अपराध में संलिप्त पाए जाने पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

रेलवे फाटक से 12 दिन आवागमन बंद

भिलाई। रेलवे प्रशासन द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के अंतर्गत कुम्हारी से भिलाई किमी।842/8-10 (कुम्हारी से भिलाई की ओर) स्थित मानव सहित समपार संख्या 430 कुगदा फाटक में बेहतर सड़क आवागमन सुविधा के लिए रोड अंडरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप यह समपार फाटक 15 से 26 फरवरी तक 12 दिनों के तक सड़क यातायात के लिए पूर्णत: बंद रहेगा। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उक्त समपार फाटक के निकट रायपुर की ओर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर समपार फाटक क्र।429 (परसदा गेट) स्थित है एवं दुर्ग की ओर लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर समपार फाटक क्र. 436 (उरला गेट) पर अंडरब्रिज निर्मित है तथा उसका उपयोग आवागमन के लिए किया जा रहा है। इसलिए समपार फाटक संख्या 430 के आस-पास से आवगमन करने वाले लोगों को असुविधा नहीं होगी।

निधन **अरविंद वर्मा**

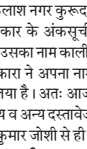

भिलाई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता राम जन्मोत्सव समिति के कैप प्रखंड के पूर्व अध्यक्ष, राधाना पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर, लिंक रोड कैप-2 निवासी अरविन्द वर्मा का आज प्रात: लगभग 3 बजे हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। उनके निधन से क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है। भाजपा नेता भोला राम साहू ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना की है।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा स्पनिता जोशी पति श्री आशीष कुमार जोशी, निवासी प्लाट नं.-34, एम.पी.सी.सी. रोड, वंदना गैस एजेन्सी, कैलाश नगर कुरूद भिलाई तह. व जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ है, कि मेरी पक्षकार के अंकसूची में उसका नाम के. स्पनिता आचार्य एवं पासपोर्ट में उसका नाम कालीदास स्पनिता आचार्य दर्ज है, विवाहोपरान्त मेरी पक्षकारा ने अपना नाम स्पनिता जोशी पति श्री आशीष कुमार जोशी रख लिया है। अतः आज से मेरी पक्षकारो के समस्त शासकीय, अद्धशासकीय व अन्य दस्तावेजो में उसका नया नाम स्पनिता जोशी पति श्री आशीष कुमार जोशी से ही जाना पहचाना जावे।

भवदीय
SHUBHAM JAIN
Advocate, Dist. Court Durg (C.G.) Durg-2112/2011, State Bar-245/2007 Mob.: 9329509424, 9630669922

पीआरजीआई सं.-CTHIN/25/A3746 यह हिंदी सांध्य दैनिक समाचार पत्र नई दृष्टिबिंद स्वामी एवं प्रकाशक आलोक तिवारी द्वारा समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 से मुद्रित करवा कर। 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से प्रकाशित संपादक आलोक तिवारी मो. 7415469100 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारण न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।